RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ.. सच

माही की गूंज

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 28 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 16 अप्रैल 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

पड़ोसी जिले आलीराजपुर में कोरोना ने दी दस्तक

शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से लगा कर्फ्यू

माही की गूंज, झाबुआ। देश भर के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां झाबुआ आलिराजपुर जिलों को पूरी तरह से लॉक डाउन किया गया था। वहीं दूसरी ओर जिला आलिराजपुर में एक कोरोना पॉजिटिव की खबर मिलते ही पूरे जिले आलिराजपुर के साथ ही झाबुआ जिले में भी इसको लेकर चिंता बढ चुकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आलिराजपुर जिले के उदयगढ में जन शिक्षक के रूप में पदस्थ व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने उदयगढ व आलिराजपुर जिले की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस थाना उदयगढ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त व्यक्ति 29 मार्च को उज्जैन से लोटा था और उसे सर्दी, खांसी, बुखार था। 9 अप्रैल से इसे आलिराजपुर में आइसोलेट वार्ड में भर्ती कर रखा था। बुधवार को इसकी कोरोना की रिपोर्ट की पुष्टि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इन्दौर की रिपोर्ट में इसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। उक्त रिपोर्ट आने के बाद आलिराजपुर जिले में हडकम्प मच गया और आला अधिकारी हरकत में आए। जल्दी ही उन्होंने उदयगढ ओर आलिराजपुर जिले की सीमा को पूरी तरह से सील किया गया। अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क मे आया था। अभी तक झाबुआ और आलिराजपुर जिले कोरोना संक्रमण से पूरी तर से मुक्त थे, लेकिन आलिराजपुर जिले में पहला मरीज मिलने के साथ ही इन जिलों में भी संक्रमण बीमारी ने दस्तक दे दी है।

कोरोना की असत्य खबर से हरकत में आया झाबुआ जिला प्रशासन

माही की गूंज, झाबुआ। झाबुआ जिले में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज अब तक नहीं मिला है, लेकिन कल एक कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया गया। हालांकि बाद में इसकी जांच में कोरोना पीडित गुजरात के दाहोद का निकला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बारिया ने बताया गुजरात के दाहोद की रहने वाली एक बालिका का इंदौर में इलाज हो रहा है, जब उससे उसका पता पूछा गया, तो उसने झाबुआ के पास दाहोद होना बताया। बस यही गलतफहमी कर्मचारी को भी हो गई और उसने लिस्ट में दाहोद झाबुआ कर दिया। जिलेवासियों को घबराने की आवश्यकता नही है। यह सब त्रुटिपूर्ण हुआ है।

3 मई के बाद हालात बिगड़े तो सीबीएसई नहीं लेगा परीक्षा

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वायरस के खिलाफलड़ाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दुविधा भी बढ़ गई है। इससे पहले 21 दिन के लॉकडाउन का असर बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ा है। सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं और परिणाम जारी करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 3 मई तक स्थितियों के सुधरने का इंतजार किया जाएगा। अगर इसके बाद भी हालातों में सुधार नहीं होता तो सीबीएसई 3 मई के बाद 12वीं की परीक्षाओं, मूल्यांकन और परिणामों को जारी करने को लेकर निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई परीक्षा आयोजित कराने के दस दिन पहले हर तरह की जानकारी साझा करेगा।

लॉक डाउन 20 अप्रैल के बाद कृषि व औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगी रियायत

नई दिल्ली, एजेंसी । कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को फिर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायतें भी शामिल हैं। 20 तारीख के बाद से कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरह बचे रहने वाले क्षेत्रों में कृषि, विनिर्माण, वित्तीय सेवा और मनरेगा गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

लॉकडाउन पर सख्त गाइडलाइन: मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर जुर्माना

कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलने जा रही है इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।

यातायात पर रोक

हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।

स्कूल, कॉलेज बंद

सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद। सभी धार्मिक स्थल बंद।

राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह ढकर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।

शादी फिलहाल नहीं, जिम बंद

सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

खेती से जुड़े काम जारी रहेंगे

खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं।

ये होंगे नियम

औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।
सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी। बस, रेल, मेट्रो पर जारी रहेगी रोक।
आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगी रोक।
कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दी गई।
20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर गतिविधियों को अनुमति।
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पुर जुर्माना।
शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।
निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है।

पहली बार मुर्दे से इंसान में फैला वायरस, दफनाए जाने का विरोध शुरू

मुंबई, एजेंसी। कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है और इसके लेकर हुए ताजा खुलासे ने चिंता बढ़ा दी है। दुनिया में पहली बार किसी मृत व्यक्ति से कोरोना संक्रमण फैलने का केस सामने आया है। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि थाईलैंड के एक डॉक्टर में कोरोना संक्रमण पाया गया है। अब पता चला है कि उसे यह संक्रमण एक कोरोना पॉजिटिव मृत व्यक्ति से मिली थी। जर्नल ऑफ फॉरेंसिक स्टडी में यह रिपोर्ट प्रकाशित गई है, ताकि दुनियाभर में इससे बचने के उपाय किए जा सकें। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों को दफनाने का विरोध भी शुरू हो गया है। थाईलैंड में अब तक कोरोना वायरस के 2500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह केस सामने आने के बाद मृत शरीर की जांच और उनका अंतिम संस्कार तक के कामों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से गाइड लाइन जारी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां मुर्दों को दहनाने की परंपरा है, वहां खतरा ज्यादा है। ऐसे शरीर में और ऐसे स्थानों पर कोरोना वायरस कई दिनों तक रह सकता है। यहां से इन्सानों के साथ ही पशुओं में संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो रहा है।

कोरोनाः मृतकों की संख्या 1,25,000 के पार

वाशिंगटन, एजेंसी। दुनियाभर में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 1,25,000 के आंकड़े को पार कर गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में चीन में इस वायरस पहला मामला सामने आया था और उसके बाद से लेकर अब तक 1,26,604 लोगों की मौत हो चुकी है।

मार्च में थोक महंगाई घटी

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार में मांग गिरने से मार्च में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर एक प्रतिशत रह गई। इससे पहले पिछले महीने में यह आंकड़ा 2.26/ था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बुधवार को यहां जारी आंकड़ों में बताया कि मार्च 2019 में 3.10 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11 हजार के पार, मरने वालों की संख्या हुई 377

1306 मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ्य

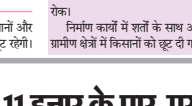

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में वैश्विक महामारी कोविड के मरीजों की संख्या ग्यारह हजार के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में ही 1076 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 11,439 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 38 मौतें दर्ज हुई हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 तक पहुंच गया है। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 76 मरीज विदेशी भी हैं। जबकि राहत भरी खबर यह है कि कोरोना संक्रमित 1306 मरीज स्वस्थ्य होकर घर वापस जा चुके हैं।

मप्रः दिल्ली भेजे 1142 सैंपलों में से 117 की आई पॉजीटिव रिपोर्ट

भोपाल/इंदौर, एजेंसी। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर में बुधवार की सुबह दिल्ली से आयी रिपोर्ट में 117 लोगों पॉजीटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 544 हो गई है। इंदौर के सीएमएचओ डॉ. प्रवीण जड़िया ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 874 पहुंच गई है जबकि इस बीमारी से अब तक प्रदेश में 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

बुधवार को इंदौर में 117 नये पॉजीटिव मरीजों के मिलने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 874 हो गई है। इनमें इंदौर के 544 के अलावा भोपाल 158, जबलपुर 12, ग्वालियर 06, शिवपुरी 02, उज्जैन 26, खरगौन 17, मुरैना 14, छिंदवाड़ा 04, बड़वानी 17, बैतूल 01, विदिशा 13, श्योपुर 03, होशंगाबाद 15, खंडवा 15, रायसेन 04, देवास 07, धार 03, सागर 01, शाजापुर 04, मंदसौर 02, रतलाम 02, सतना 02, टीकमगढ़ 01 तथा एक मरीज अन्य राज्य का शामिल हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना से संक्रमित 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में इंदौर के सबसे अधिक 37, भोपाल 05, उज्जैन 06, खरगौन 03, छिंदवाड़ा 01 और देवास का एक व्यक्ति शामिल हैं।

भोपाल में गैस से बचे, कोरोना से हारे

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक यहां इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 757 पर पहुंच गई है। इस महामारी से प्रदेश में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 37 लोगों की जान इंदौर में गई है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 लोग कोरोना का शिकार बने हैं। राजधानी में जिन पांच लोगों को इस महामारी ने अपना शिकार बनाया है वो सभी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित थे। करीब 36 साल पहले हुए भोपाल गैस त्रासदी के दौरान इन पांचों पीड़ितों की जान बच गई थी लेकिन अब कोरोना महामारी से ये बच नहीं सके। इन सभी की मौत निजी अस्पताल में हुई। इनका भाग्य देखिए कि उन्हें भोपाल मेडिकल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में भी कदम रखने का मौका नहीं मिल सका। बीएमएच आर सी खास तौर से गैस त्रासदी से जुड़े पीड़ितों के लिए था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस कोविड-19 मरीजों के लिए समर्पित कर दिया।

आपका घर में रहना आपके साथ ही देश के लिए भी जरूरी है

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

विश्वव्यापी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से इस समय पूरा विश्व ग्रसित है और इसके संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसके बारे में एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि, कोविड-19 जब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने नहीं जाते। छोटा सा संदेश अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन बावजूद इसके हमने इसका पालन नहीं किया। नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूरन लॉकडाउन 2 की घोषणा करना पड़ी प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया था की भारत में कोरोना के पहले संक्रमण का पता लगने के पूर्व ही विदेशों से आने वाले सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग करना प्रारंभ कर दिया था और 500 केस होने के पूर्व ही पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया था। एक और विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अर्थव्यवस्था को देश के नागरिकों से ज्यादा तवज्जो दी लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, जान है तो जहान है और लॉकडाउन की तुरंत घोषणा कर दी। जिसके लिए पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के इस फैसले की तारीफ हो रही है। अरबों-खरबों की अर्थव्यवस्था की बगैर चिंता किए भारतीय प्रधानमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। लेकिन क्या हम अपने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का पालन कर रहे हैं? आज देश में लगभग 12हजार संक्रमण के मामले सामने आ चुके है, जिसमें से ज्यादातर मामला संक्रमित व्यक्ति की गलत जानकारी या पहचान छुपाने के कारण सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने समय से पूर्व ही जब देश में एक भी केस नहीं था तभी देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग चालू कर दी थी, बावजूद इसके यह संक्रमण फैलना इस बात को दर्शाता है कि, पहले संक्रमित व्यक्ति ने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जांच एजेंसियों को गुमराह किया, जिससे इस भयावह वायरस ने हिंदुस्तान की धरती पर पैर पसारे। यही नहीं प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के पहले चरण में की गई अपील का पालन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। निसंदेह भारत जैसे विशाल देश में इतनी अधिक जनसंख्या के होने के बावजूद संक्रमण इतना कम फैलना हमारी सफ्तता को इंगित कर रहा है और जिसके लिए पूरे विश्व में भारत की तारीफभी हो रही है। लेकिन इसके लिए देश ने कितनी बड़ी रकम चुकाई है, शायद इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरे देश की मेहनत पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे असामाजिक तत्वों को सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए और अभी भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहा है या पुलिस और डॉक्टर को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों को इंसान कहलाने का हक भी नहीं है। जिस प्रकार हमारे देश के जवानों के सीमा पर खड़े होने से देश सुरक्षित है, उसी प्रकार आपको अपने घर में रहने से भी देश सुरक्षित है। क्योंकि इससे न केवल आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि देश को भी इस महामारी से बचा रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन के दूसरे चरण को भी गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करें ताकि तीसरे चरण की आवश्यकता ही ना पड़े।

खतरे में मालवा-निमाड़: इंदौर में मिले 121 नए केस, बाकी जगहों पर मिले 27 नए मरीज

इंदौर, एजेंसी। इंदौर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह में 121 नए केस मिले हैं। कोरोना का खतरा मालवा-निमाड़ में भी बढ़ रहा है। यहां एक दिन में 27 नए केस मिले हैं। इंदौर-उज्जैन के अलावा अब खंडवा में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगर और शाजापुर में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। खंडवा की मक्का मस्जिद में कनॉटक के जमातियों के संपर्क में आए 30 नमाजियों में से 9 और एक अन्य मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 15 हो गई है। सरकार की गाइडलाइन के चलते 10 से अधिक पॉजिटिव मरीज होने पर जिला अरिज से रेड जोन में पहुंच गया है। जिले के 50 से ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है।

बड़वानी में सीएमएचओ भी चपेट में

बड़वानी में सीएमएचओ डॉ. अनीता सिंगारे, महिला स्वास्थ्यकर्मी व सेंधवा निवासी 15 वर्षीय कि शोर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 17 हो चुकी है। 3 अप्रैल को सेंधवा के तीन लोग संक्रमित पाए जाने के बाद सीएमएचओ वहां पहुंचे थीं। साथ ही सेंधवा के मरीजों के बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान व संभवतरू उन्हीं से संक्रमित नर्स के साथ सीएमएचओ के संपर्क में आने का संदेह है। इधर, मंगलवार को कलेक्टर अमित तोमर घर पर क्वारंटाइन हो गए। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन सहित चार डॉक्टर भी क्वारंटाइन हो गए।

शाजापुरः पुलिस आरक्षक और दो अन्य पॉजिटिव

शाजापुर से जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें पुलिस आरक्षक, दो महिलाएं और दो अन्य ग्राम मोचीखेड़ी के हैं। एक महिला इंदौर निवासी है। वह कि सी आयोजन के लिए ग्राम मोचीखेड़ी आई थी। इन्हें मिलाकर संक्रमित मरीजों की संख्या चार हो गई है।

नलखेड़ा में 3 जमाती पॉजिटिव

आगर-मालवा के नलखेड़ा में तीन मरीज संक्रमित पाए गए। ये तीनों जमाती हैं, जो गत सप्ताह नलखेड़ा में क्वारंटाइन किए गए 12 जमातियों में शामिल हैं।

धारः नर्स संक्रमित, अब तक तीन

धार में नर्स की रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आई। वह निजी अस्पताल में सेवाएं दे रही थी और कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के दौरान संपर्क में आई थी। पहला मरीज उज्जैन गया था और वहां से संपर्क में आने के कारण उसकी रिपोर्ट 8 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। दूसरा मरीज पुलिस आरक्षक 12 अप्रैल को सामने आया था।

भोपाल, इंदौर और उज्जैन में सख्ती बरतेगी सरकार

लॉकडाउन अवधि में राज्य सरकार भोपाल, इंदौर और उज्जैन में सख्त नजर आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मंगलवार को यह निर्देश दिए। तीनों शहरों में कंटेनमेंट एरिया में अधिक सख्ती करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान देने को कहा है। वहीं, कमजोर वर्ग को खाद्य सामग्री देने के लिए सरकारी उचित मूल्य दुकानें 12 घंटे खुली रखने के निर्देश दिए।

राहुल गांधी ने कहा- धीरे-धीरे कारोबार करने की अनुमति मिले

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन लाखों किसानों, प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है। जिससे 'चतुराईश् से निपटने की जरूरत है और धीरे-धीरे काम-धंधों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सभी को कष्ट दे रहा है। लाखों किसानों, प्रवासी मजदूरों एवं व्यापार करने वालों को यह अनकहा दुख और पीड़ा दे रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि इस लॉकडाउन से 'चतुराईश् से आगे निकलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोरोना के हॉटस्पॉट पर ज्यादा से ज्यादा जांच करने और धीरे-धीरे कारोबारी गतिविधियों को मंजूरी दी जाए। उनके इस ट्वीट को करीब 14 हजार लाइक्स मिले हैं।

गरीब को हर बार भगवान भरोसे छोड़ते हैं मोदीः प्रियंका

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के पहले दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए बुधवार को कहा कि वह गरीब को ध्यान में रखकर फैसले नहीं लेते जिससे हर बार गरीबों को ही गहरी चोट पहुंचती है। श्रीमती वाड्रा ने ट्वीट किया, 'आखिर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है। उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते। उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी। उनके लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया।' उन्होंने कहा, 'उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, स्टॉक का राशन खत्म हो रहा है, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं-घर गाँव जाना चाहते हैं। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अभी भी सही प्लानिंग के साथ इनकी मदद की व्यवस्था की जा सकती है। मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। नरेंद्र मोदी जी भगवान के लिए इनकी मदद कीजिए।'

देपालपुर के पास से आए मजदूरों की स्वास्थ जांच कर दी हिदायत

माही की गूंज, बनी। ऋषभ गुप्ता

कचराखदान पंचायत के ग्राम जमुनिया के कटारा फलिये के लोग रात्रि तीन बजे गांव बनी में पहुंचे। जैसे ही ये सूचना गांव के कोटवार को मिली। उसने तत्काल सहायक सचिव को सूचना दी। सहायक सचिव,ओर ए,ऐन,एम,ने मौके पर जाकर जानकारी सही होना पाया। जिस पर रायपुरिया पुलिस और रायपुरिया के डॉ. कटारा को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और डॉ.कटारा की टीम ने पहुंचे और सभी की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें घर में ही रहने की हिदायत दी गई।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि देपालपुर के समीप गांव में मजदूरी कर रहे करीब चार गांवों के लोग आयशर गाड़ी किराये से लेकर अपने गांवों तक कैसे पहुंचे होंगे। लॉकडाउन के बाद भी इन लोगों को कहीं पर नहीं रोक गया और न ही किसी प्रकार की कोई जांच की गई। कोरोना संक्रमण के चलते पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है और इन लोगों का अपने गांव तक पहुंचना प्रशासन की लापरवाही उजागर करता है।

तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध

माही की गूंज, झाबुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) रोग के फेलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायरस के संक्रमण को रोकने एवं बचाव के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने को प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण ड्रॉपलेट के द्वारा ही हो सकता है इसलिए जिला कलेक्टर ने तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार झाबुआ जिले की सीमा में कोई भी व्यापारीध्दुकानदारध् संस्थानध् व्यक्ति तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का न तो भंडारण कर सकेगा और न ही विक्रय कर सकेगा इसके साथ ही जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति इन पदार्थों को न तो अपने साथ रख सकेगा और न हीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकेगा उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भ्रष्टाचारियों और माफियाओं का नहीं कोई जमीर

शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर जश्न मनाने वाले के विरुद्ध होनी चाहिए एफआईआर

माही की गूंज, थांदला। मुकेश भट्ट

चीन से उत्पन्न हुआ कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा विश्व लड़ रहा है, तो वहीं हमारे केंद्र व प्रदेश की सरकार भी इस संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रयास कर रही है। शासन-प्रशासन के निर्देशों व लॉकडाउन का पालन कर आमजन भी घरों के अंदर रहकर कई परेशानियों का सामना कर परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि, हे ऊपर वाले इस संक्रमण से मुक्ति दिलाकर देश की आबो हवा को फिर से स्वच्छ कर दे और आमजन फिर से अपनी गति पकड़ कर देश का विकास करने लग जाए।

परंतु इस विकट स्थिति से निजात दिलाने का नैतिक कर्तव्य देश के हर नागरिक का है, तो वहीं जिनके जिम्में कुछ प्रशासनिक जवाबदेही हो, समाज-संगठन का नेतृत्वकर्ता हो या फिर किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, उनका नैतिक कर्तव्य थोड़ा और अधिक बढ़ जाता है। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे अधीनस्थ इनको देखकर या उनके दिशा निर्देशन में देश को खतरे में डाल दे। ऐसी विकट स्थिति में सभी समाज-संगठन, राजनीतिक दल या किसी भी धर्म के धर्मगुरु सभी को अपनी देश हित के लिए महत्वपूर्ण जवाबदेही को समझना आवश्यक होता है।

तबलीगी जमात की तर्ज पर ही पारसिंग मुणिया ने अपनी जमात को इकट्ठा कर मनाया जश्न

दिल्ली में तबलीगी जमात के मौलाना ने, जहां पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रहा था और शासन के सख्त निर्देश के बाद भी मौलाना मोहम्मद साद ने देश विरोधी अपनी करतूतों को दिखाकर हजारों लोगों को बरगलाकर देश को खतरे में डालने का प्रयास किया। हम पहले भी कह चुके हैं कि, ऐसे व्यक्तियों का ना कोई धर्म होता है न ही कोई जमीर। इसलिए ऐसे मौलाना को मौलाना कहलाने का हक भी नहीं है। मौलाना ही नहीं वरन् किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो या कोई जवाब देह पद पर अगर वह देश को किसी भी समय खतरे में डालने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियो को देशद्रोही ही माना जाएगा।

झाबुआ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा थांदला के मैनेजर पारसिंग मुणिया ने बैंक के अपने अधीनस्थ जमात के 12 से 15 अधिकारी, कर्मचारी व ईष्ट मित्रों को 3 मार्च को शाखा में इकट्ठा कर शासन के सारे निर्देशों का मखौल उड़ाकर उस समय अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। जब पूरा देश खून के आंसू रो रहा है और कोरोना संक्रमण से तोबा के लिए प्रार्थना कर रहा है।

जन्मदिन का जश्न मनाकर सीसीबी एवं सहकारी संस्थाओ के इन जमातियो ने ही सोशल मिडिया पर किए फोटो वायरल।

3 मार्च को सीसीबी शाखा थांदला में पदस्थ मैनेजर परसिंग मुणिया का जन्मदिन था। जन्मदिन का जश्न मनाने हेतु अपने सभी अधीनस्थ काकनवानी आजास संस्था के प्रबंधन गुलाबसिंह निनामा, खजूरी संस्था के प्रबंधक निहालसिंह कन्नौज, परवलिया संस्था के प्रबंधक अर्जुनसिंह नायक, धामनी संस्था के प्रबंधक राजेंद्रसिंह राठौर, थांदला सीसीबी शाखा के लिपिक बहादुरसिंह राठौर आदि के साथ करीब 12 से 15 अधिकारी एवं अपने मित्रों को बुलाकर जन्मदिन का जश्न मनाया। जिसमें सोशल डिस्टेंसिग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बर्थडे पार्टी जश्न में केक काटा, साथ ही शराब व मांस की पार्टी भी की। उक्त जश्न में सबसे बड़ी बात यह रही कि इन्होंने केक काटने से लेकर शराब पीने तक के फोटो खींचे और इन्ही अधिकारियों ने बाद में सोशल मीडिया पर बर्थडे जश्न रूपी पार्टी के फोटो वायरल कर सारी संवेदनाओं का हनन किया और जिले को स्वयं ने ही बता दिया कि, वह कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए किस तरह से अपनी जवाबदारियों का निर्वहन कर रहे है और जिले को खतरे में डालने का प्रयास भी कर रहे है। इन जवाबदारो की हरकतों को जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में निंदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि, उस तबलीगी जमात में जिस तरह से मौलाना मोहम्मद साद ने बड़ी संख्या में जमातियों को इकट्ठा कर देश को खतरे में डालने का प्रयास किया, उसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार के मद में इतने मदहोश हो गए कि वे इस विकट परिस्थिति को भूल तबलीगी जमात से भले छोटा रूप हो पर अपनी जमात के लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाया। कहने को यह रूप भले से छोटा हो, पर अनजाने में भी जश्नकर्ताओं में से किसी एक के कारण भी संक्रमण जैसी स्थिति बनती तो यह तबलीगी जमात से भी बड़ा रूप धारण कर देश को खतरे में डाल सकती थी।

इनके जिम्मे भी थी कोरोना से जंग जीताने की जवाबदेही

बता दें कि, वर्तमान में शासन के निर्देशन में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से तीन-तीन माह का खाद्यान्न वितरण हो रहा है और इन अधिकारियों के जिम्मे भी कोरोना से जंग जिताने की बडी जवाबदेही थी। इन अधिकारियों के ही दिशा-निर्देशन व इनके निरीक्षण में ही अधीनस्थ संस्थाओं में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है और इनकी यह एक गलती भी उस खाद्यान्न वितरण के साथ संक्रमण का कितना बड़ा रूप ले सकता था? यह विचारणीय है। इस गलती को किसी भी स्तर पर शासन - प्रशासन को नजरअंदाज नहीं कर सीसीबी संस्था के इन जमातियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सिर्फआमजन को संतुष्ट करने के लिए निलंबन व नोटिस देकर जांच को अधर में डालकर कार्रवाही की खानापूर्ति नही करें। न हीं तो हो सकता है इसका अनुसरण कर कोई और ऐसी गलती कर खतरा उत्पन्न करें।

वर्तमान में सरंक्षण देना कही शासन-प्रशासन को नही पड़ जाए महंगा

पारसिंग मुणिया का भ्रष्टाचार व साठगांठ की दुनिया में बड़ा बोलबाला है बता दें कि बामनिाया में पदस्थ रहे पारसिंग मुणिया ने राजेंद्र पिता राम नारायण लोहार के खाते की राशि राजू मोतीलाल पाटीदार के बंद पड़े खाते की राशि बताकर फर्जी रूप से आहरण करवा दी। इतना ही नहीं इनकी ही देखरेख में खवासा संस्था में रासायनिक खाद सेल्समैन द्वारा बड़ी मात्रा में बेच दिया। लेकिन बेचा हुआ रासायनिक खाद भी राशि जेब में रख सुपरवाइजर प्रकाश त्रिपाठी व शाखा में मैनेजर रहते बिके हुए माल को आमद में बताया जा रहा था। शिकायत के बाद सुपरवाइजर के साथ पारसिंग मुणिया ने भी निरीक्षण का हवाला देकर 12 लाख 76 हजार 142 रुपए का रासायनिक खाद कम पाया गया। जिसकी रिकवरी सेल्समैन से की गई। बताते हैं कि सेल्समैन ने अपनी जमीन बेच कर उक्त पूरी राशि नगदी कुछ गवाहों के समक्ष दे दी थी, परंतु पारसिंग मुणिया ने 30 मार्च 2017 में किसानों का हवाला देकर उनके नामे खाद को बाकी बताकर लागू जमा खर्च में केश पान 75 पर रजिस्टर पर दर्शाया। कंप्यूटर नं. 13880083 पी 145 में दर्शाया गया। जबकि उक्त राशि चालान एवं कैश जमापर्ची के साथ बैंक में जमा होना थी।

उक्त पूरी राशि पारसिंग मुणिया हजम कर गया। बताया जा रहा है तो, वहीं ऐसे कई भ्रष्टाचार व सांठगांठ कर पूरे मामले को रफा-दफा करने वाले उक्त भ्रष्टाचारी का कोई जमीर ही नहीं है जो पूर्व में भी अपने भ्रष्ट कारनामों के कारण कई बार निलंबित भी हो चुके हैं को, वर्तमान में भी संरक्षण देना आमजन के साथ शासन-प्रशासन को भी महंगा पड़ सकता है।

अफवाह के चलते गांव की सुरक्षा में जुटे ग्रामीण

माही की गूंज, खच्चरटोडी।

शनिवार रात को ग्रामीण अचंलों मे अफवाह आग की तरह तेजी से फैली। जिसमें लोगों के बीच यह बात पहुंची कि पडोसी राज्य गुजरात से बोलेरो पिकअप भरकर बडी संख्या में लुटेरे चोरी के लिए गांव में धावा बोलेंगे। मेघनगर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण इलाके खच्चरटोडी, नया गांव खालसा, नईटोडी ,जामनिया, ढाढनिया, डुण्डका, नया गाँव जागीर , रंभापुर ,वानियापाडा, पिपलोदा बड़ा, पोचक,बेडावली झाडटोडी, गडुली ,झाराडाबर, मालहात, आदि गांवों मे अपवाह तेजी से फैली। ग्रामीणजन अफवाह से डर गए। गांव की एक जगह लट्ठ, तलवार बूंदक आदि हथियारों के साथ इकट्ठा होकर गांव की सुरक्षा मे लग गए। इकट्ठा होने से सोशल डिस्टसिग का ध्यान नहीं रखा गया। जिसे संक्रमण की सम्भावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण अचंल में अफवाह के कारण डर का माहौल बन गया। लोग पूरी रात जागते रहे।

गुजरात बॉर्डर पर स्थित ढाढनिया ग्राम पंचायत में सरपंच पति धारु ने बताया की आसपास की गांवों से फोन आए कि गुजरात में चोरी हो गई है। अब अपने इलाके में चोरी की वारदात होगी। इस बात से गांव में भय का माहौल बन गया। गुजरात बॉर्डर पर लगी पुलिस से सम्पर्क किया तो वहां से आश्वत किया की चोरी की वारदातें होने की बात मात्र अफवाह है। इसके बाद माहौल शान्त हुआ। यही बात डुण्डका, जामनिया, झाराडाबर,मालहात के लोगों ने कही। वही खच्चरटोडी, जागीर, नया गांव खालसा में यह अफवाह फैली की पास की गांव वानिया पाडा में करीबन 50 लोगों ने गांव को घेर लिया है और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे है। इससे लोग डर गए और हथियारों के साथ अपनी गांव की सुरक्षा में लग गए।

खच्चरटोडी सरपंचपति प्रदीप गणावा ने बताया कि आस -पास की गांवों में शोर होने से गावं के लोग डर गए। अफवाह के कारण सतर्कता के तौर पर सभी रात भर जागे।

पुलिस ने गांवों में कराई मुनादी

रविवार को पुलिस ने गावों में ऐलान करवाया कि गांवों में चोरी की घटनाएं की बातें जो सामने आ रही है। वो पूरी तरह से झूठ है। चौकी प्रभारी हरिसिंह चुंडावत ने कहा कि इसी अफवाहों पर ध्यान न दे। अपने क्षेत्र में चोरी की एक भी घटना नहीं हुई । कोई भी सोशल मीडिया पर कोई अफवाह न फैलाए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

500 रुपए में मौत आई बैंक के द्वार, ऐसे लॉक डाउन का क्या मतलब ?

माही की गूंज, पेटलावद/बामियान।

लॉक डाउन पूरे देश में 03 मई तक तो बढ़ गया लेकिन लॉक डाउन बढ़ाकर उसका पालन करवाने वाले प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की योजना के कारण लॉक डाउन पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये मदद के रूप में डाले ताकि इस समय में लोगों को मदद मिल सके। लेकिन ये 500 रुपए कहीं मौत तो नहीं ले कर आ रहे है, यह कह नहीं सकते। संपूर्ण जिले के नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में लॉक डाउन के चलते आमजन घरों में रह कर शासन के नियमों का पालन कर रहे है, लेकिन जनधन के खातों में 500 रुपए निकलने के लिए बड़ी मात्रा में ग्रामीण लोग बैंक और कियोस्क सेंटर पर पहुंच रहे हैं। साथ ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और कर्मकार मंडल के हितग्राहियों के खातों में भी राशि आई है। उक्त राशि निकालने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिसमें कई ग्रामीणों के खाते बिना लेन देन के बन्द हैं, तो कई लोगों के खाते आधार लिंक ही नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा पैसे डालने की सूचना पर लोग बैंक और कियोस्क सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जबकि कई कियोस्क सेंटरों द्वारा ग्रामीण इलाकों में पहुंच कर राशि वितरण की जा चुकी हैं। फिर भी ग्रामीण नगर में पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के बीच ऐसी भी अफवाह हैं कि शासन ने जो राशि खातों में डाली हैं, वो नही निकली तो राशि सरकार वापस ले लेगी। प्रधानमंत्री ने बुजुर्ग लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी है, लेकिन बैंक और कियोस्क सेंटर पर पहुंच रहे अधिकांश लोग बुजुर्ग है। एक साथ आ रही भीड़ न तो बैंक से न ही कियोस्क सेंटर वालों से नियंत्रित हो रही है। अधिकांश लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ही आ रहे हैं। कही ये शासन 500 रुपए मौत ना बांट जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन द्वारा आप तक जिले भर में लोगों की स्क्रिनिंग नहीं हो सकी हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान दे कर बैंकों से सामंजस्य स्थापित कर कोई कार्य योजना बनानी होगी। न ही तो कोरोना कब दबे पांव आकर अब तक की मेहनत पर पानी फैर कर मौत का तांडव कर जाएगा। इसका कोई भरोसा नहीं।

दूध कंपनी नहीं कर रही नियमित खरीदी, पशुपालक परेशान, लॉक डाउन से पशुओं के चारे व पौष्टिक आहार का संकट

माही की गूंज, खच्चरटोड़ी।

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन है। इसके कारण पशुपालकों को काफी परेशानी हो रही है। सहकारी दुग्ध संघ सांची पशुपालकों से नियमित रूप से दुग्ध नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के बाद मिठाई एवं चाय की गुमटिया बंद हो गई है। ऐसे में संघ दुग्ध की खपत नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण पशुपालकों से जो दुग्ध खरीदा भी जा रहा है। वह भी कम भाव में खरीदा जा रहा है। लॉकडाउन के पहले 7रुपए प्रति फेट के हिसाब से दुग्ध पशुपालकों से खरीदती थी लेकिन लॉकडाउन में भाव कम कर 6 रु प्रति फेट से खरीद रही है। इससे पशुपालको को आर्थिक रुप से काफी नुकसान पहुचं रहा है ।

भूसा नहीं मिलना भी पशुपालकों के सामने बडी समस्या पैदा कर रहा है। मवेशियों के लिए पशुआहार जुटाने में काफी परेशानी हो रही है। पशुपालक अप्रैल माह में भूसे का स्टाक हर साल करते है, जो अब खत्म होने जा रहा है। भूसा विक्रेता का कहना है कि भूसा अन्य जिलों से आता है। भूसे की गाडियों को परमिशन तो है लेकिन मजदूर नहीं होने एवं अधिकांश जिलों की सीमा पूरी तरह से सील होने से भूसे की गाडियां एक दो की संख्या में ही आ रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर टेम्पो, पिकअप एवं अन्य वाहनों के बंद होने से भूसा पशुपालक नही ले जा पा रहे है।

पशुपालक दिनेशचन्द्र खतेडिया का कहना है कि एक ओर तो सांची संघ मनमानी करते हुए हमसे नियमित रुप से दुग्ध नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर पशुओं को खिलाने वाले पौष्टिक आहार खली भी महंगी मिल रही है। भूसे की काफी किल्लत आ रही है। शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

बामनिया के युवक ने बनाई ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन

नि:शुल्क उपस्वास्थ्य केंद्र पर भेंट की

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन-प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। वहीं अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी इस विकट परिस्थिति में अपना अहम योगदान दे रही हैं। इसी क्रम में इंजीनियरिंग के छात्र अंकित दिनेश भाटोदरा ने महज दो दिन तक प्रयास कर आटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन बनाकर कोरोना की जंग लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक महत्वपूर्ण हथियार प्रदान किया है।

मशीन को सोमवार को बामनिया स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वारा पर लगाया गया। जिससे स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाला हर मरीज सैनिटाइज होगा। इस मशीन में एक लाइट, एक अलर्ट घंटी व 20 लीटर का टैंक लगाया गया है, जिससे 200 से अधिक लोग सैनिटाइज हो सकेंगे। यह मशीन आटोमेटिक सेंसर्स के जरिए काम करती है। जैसे ही कोई व्यक्ति मशीन में प्रवेश करेगा, सेंसर्स मशीन को ऑन कर देगा। व्यक्ति के निकलने के बाद मशीन खुद ही बंद हो जाएगी।

बैटरी से चलती है मशीन, करंट का खतरा नहीं

अंकित भाटोदरा ने बताया कि इस मशीन को बनाने में लगभग 16 हजार की लागत आई है। यह मशीन एक चौंबर की तरह है जिसमें स्प्रे करने वाली मशीन लगी हुई है। जो दोनों ओर से अंदर घुसने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के जरिए उसे सैनिटाइज करती है। इस मशीन को चालू करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है यह बैटरी से चलती है। जिससे सैनिटाइज के समय करंट का खतरा नहीं है। डॉ. मनीष सोलंकी, मेडिकल ऑफिसर, बामनिया ने जानकारी देते हुवे बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंजनिंयरिग के छात्र द्वारा बनाई गई मशीन को स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया है। मशीन से सैनेटाइजर का छिड़काव मरीज पर होगा। इससे वायरस से बचाव में काफी मदद मिलेगी।

दूसरी जगह से भी मिले आर्डर

युवा अंकित द्वारा बनाई गई मशीन के बामनिया उप स्वास्थ्य केंद्र लगने की जानकारी के बाद अन्य स्थानों से खास कर निजी एवं शासकीय अस्पतालो से अंकित को आटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन लगाने के लिए संपर्क कर रहे हैं , इससे पहले भाटोदरा परिवार के भतीजे जो अलीराजपुर में रहता है आटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन बनाकर गाँव का नाम रोशन कर चुका है , अंकित की सफलता के बाद नगर में सभी ने इसको सराहा।

समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई शुरू

भीड़ न हो इसलिए 6 किसानों को एसएमएस कर बुलाया

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

लॉक डाउन में क्षेत्र के किसान जिन्होंने अपनी गेहूं की फसलें काटकर घरों में रखी थी। मंडी मार्केटिंग आदि बंद होने से किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब मध्य प्रदेश शासन के आदेश से सारंगी खरीदी केंद्र पर शाखा प्रबंधक संजय रोहित सिंग ने तोल कांटे का विधिवत पूजन पाठ कर खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया। संस्था प्रबंधक मनोहर लाल वर्मा ने बताया समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। खरीदी केंद्र पर उन्हीं किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा जिन किसानों ने पूर्व में संस्था में पंजीयन कराया है। वर्मा ने यह भी बताया कि इस लॉक डाउन में गेहूं खरीदी के समय डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। इसके लिए खरीदी केंद्र पर उन किसानों को ही गेहूं बेचने के लिए बुलाया जाएगा। जिनको 1 दिन पूर्व मोबाइल मैसेज दिया जाएगा। मैसेज भी केवल 6 किसानों को दिया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा सके। केंद्र पर फिजिकल डिस्ट्रेसिंग के लिए गोल घेरे बना दिए गए हैं। हाथ धोने के लिए साबुन पानी का इंतजाम किया गया है। कर्मचारी मास्क बांधकर रहेंगे। खरीदी के लिए बारदान और सैनिटाइजेशन के लिए सामग्री उपलब्ध है। किसानों से अपील की गई है कि वह एसएमएस मिलने परी केंद्र पर आए तय तारीख पर आने पर ही उपार्जन किया जाएगा। खरीदी केंद्र के उद्घाटन अवसर पर शाखा प्रबंधक संजय रोहित सिंह संस्था प्रबंधक मनोहर लाल वर्मा नोडल अधिकारी छगन सिंह भाबर शाखा पर्यवेक्षक केके ओझा सहायक समिति सेवा शेर सिंह राठौर कंप्यूटर ऑपरेटर संजय लच्छेटा हैमाल तुला ऊटी आदि उपस्थित थे।

युवा इंजीनियर ने जिला अस्पताल में लगाई सैनिटाइजेशन मशीन

माही की गूंज, झाबुआ। कोरोना महामारी से बचाव में जुटे पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, चिकित्सक, वार्ड बॉय, नर्सेस, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी, सफाई कामगार दिन-रात अपनी सेवाएं दे रहे है। इस जानलेवा और भयावह बीमारी से इन देश सेवकों की सुरक्षा करने का भी जिम्मा भी देश के नागरिकों का ही है। जिसे बखूबी समझते हुए शहर के गोपाल कॉलोनी में रहने वाले युवा रोबोटिक इंजीनियर पवनेन्द्रसिंह सिसौदिया ने इन देशसेवकों के लिए सैनिटाइजर मशीन जिला चिकित्सालय में लगाई है। इसका मंगलवार को शुभारंभ सांसद गुमानसिंह डामोर, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, शैलेष दुबे, शांतिलाल बिलवाल, ओमप्रकाश शर्मा आदि के आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर नाना राठौर, भूपेश सिंगोड़, जितेन्द्र पंवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस बारिया, डॉ. बीएस बघेल, डॉ. सावन चौहान, प्रेम डोनियल आदि उपस्थित थे। संचालन बबलू सकलेचा ने किया।

अम्बेडकर जयंती पर कर्मवीरों का किया सम्मान

माही की गूंज, झाबुआ। जय भीम जाग्रति समिति झाबुआ ने मंगलवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती लॉकडाउन के नियमानुसार मनाई। गोपाल कॉलोनी में बाबा साहब के चित्र पर लोगों ने पुष्प माला अर्पित की। इस अवसर पर कोरोना वायरस के इस दौर में लगातार कार्य करने वाले कर्मवीरों का समिति के सदस्यों ने सम्मान किया।

समिति के अध्यक्ष एमएल फुलपगारे ने बताया कि कोरोना की जंग में अपना योगदान देने वाले कर्मवीरों का समिति के सदस्यों ने सम्मान किया है। इस अवसर पर सफाईकर्मी कल्लु भाई नाडिया तथा संगीता नाडिया को पुष्प मालाओं व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान के पूर्व समिति के सदस्यों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण व द्वीप प्रज्ज्वलित करते हुए उन्हें याद किया। नन्हें बालक ईश बैरागी ने स्वच्छता बनाए रखने व घर पर रहकर कोरोना को हराने जैसी सीख देते हुए पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग को लोगों ने जमकर सराहा। कार्यक्रम में रमेश वैष्णव, कृष्णा वैष्णव आदि उपस्थित थे।

कीटनाशक पीने से महिला की मौत

माही की गूंज, थांदला। ग्राम मानपुर में सोमवार को अज्ञात कारणों के चलते 27 वर्षीय महिला ने कीटनाशक पी लिया। उल्टी होने पर परिजन उसे शासकीय अस्पताल लाए, जहां उसे अन्यत्र रैफर कर दिया गया। लॉकडाउन के चलते दाहोद के अस्पताल बंद मिले। बाद में महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक पप्पी पति वाला खड़िया निवासी मानपुर के शव का थांदला में पोस्टमार्टम किया गया। मृतका की दो वर्षीय लड़की भी है। मामले की जांच स्थानीय थाना प्रभारी कर रहे हैं।

प्रशासन फंसा कालाबाजारी के जाल में

कोरोना के डर से ज्यादा जनता पर कालाबाजारी की मार, गरीब लाचार

माही की गूंज, थांदला।

आखिर क्या कारण है कि थांदला की पुलिस व प्रशासन दोनों निर्धारित समय के बाद नगर की गलियों में सब्जी बेचने वाले छोटे गरीब व्यवसायियों को तो कानून नियम का हवाला देकर धंधा बन्द करवा देता है। परन्तु बड़े मुनाफाखोर व्यापारी जो अनुमति की आड़ में दिन भर पर्दे के पीछे प्रतिदिन हजारों का व्यवसाय ही नहीं कर रहे है अपितु मुनाफाखोरी, कालाबाजारी कर ऊंचे दामों पर सामग्री का विक्रय छोटे दुकानदारों से लेकर आम नागरिकों के साथ कर अपनी तिजोरियां भर रहे है। यही नहीं ऐसे बड़े व्यापारी बेसमय अल सुबह से देर रात तक ऐसी सामग्री भी मोटा मुनाफा लेकर दे रहे हैं, जो लॉक डाउन में प्रतिबंधित है। पर ऐसे व्यापारियों पर पुलिस, प्रशासन, खाद्य विभाग के जिम्मेदार अमले की निगाह आखिर क्यों नही जा रही है? उन्हें कानून के नियमों का पाठ क्यों नही पढ़ाया जा रहा है? आखिर उनके उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में प्रशासन मौन क्यों है?

अनेक व्यापरियों के घर दुकान एक होने से वे भी बड़े पैमाने पर अनुमति के समय का दुरुपयोग कर 24 घण्टे मुनाफाखोरी कर बड़े पैमाने पर व्यवसाय में लिप्त हैं, तो अनेक व्यापारी जिनके घर दुकान अलग है। वे अपनी दुकानों के शटर बन्द कर अंदर बैठकर भी मोबाइल के माध्यम से आर्डर लेकर माल पैक कर क्रेताओं को बुलवाकर समय बेसमय डिलेवरी प्रदान कर मुनाफाखोरी कर रहे है।

इस तरह आवश्यक सामग्री के नाम तम्बाकू व अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार जमकर अधिक दामों में किया जा रहा है।

भाव आसमान पर

शासन-प्रशासन ने केवल आवश्यक खाद्य सामग्री की बिक्री करने हेतु एक निर्धारित समय नियत कर व्यापारियों को अनुमति प्रदान की है। उसमें भी यह स्पष्ट किया है कि वे निर्धारित मूल्यों पर ही आमजन को सामग्री उपलब्ध कराएंगे। परन्तु थोक व्यापारी आवश्यक खाद्य सामग्री के अलावा प्रतिबंधित सामग्री जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू पाउच आदि भी छोटे व्यापारियों को मोटा मुनाफा लेकर इस तर्क के साथ बेच रहे है कि यह प्रतिबंधित वस्तु ऊंचे भाव पर खरीदना पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट व पुलिस चौकियों की निगरानी से बचाकर या पैसे देकर लाना पड़ रही है। इस तरह यह मुनाफाखोर व्यापारी शासन-प्रशासन व ईमानदारी से भूखे प्यासे रहकर ड्यूटी निभा रहे पुलिस जवानों को भी अपने मुनाफे के लिए बदनाम कर रहे है।

ऐसा मोटा मुनाफा ले रहे है

लगभग दोगुने दाम पर हर चीज बिक रही है। जैसे 34-35 की शक्कर 50 से 60 रुपए किलो, सोया तेल 90 के बजाय 100-110 से लगाकर 120 तक, 85 से 90 तक कि तुअर दाल को 100 व 110 तक, 360 का बीड़ी का पुडा 430 में, विमल पाउच पैकेट 125 के स्थान पर 210 से 220 तक बेच रहे है। जिससे छोटे व्यापारी अपना मुनाफा चढ़ाकर और ऊंचे दामों पर जनता को दे रहे हैं।

बाजार में दिखाई दे रही यह भीड़ इस बात की गवाह है कि व्यापारी किस तरह कालीबाजारी कर अधिक दामों में इन्हे सामान उपलब्ध करवा रहे है।

तोल व मोल दोनों में लूट

थांदला के दशहरा मैदान से लेकर पिपली चौराहा, कुम्हारवाड़ा, गांधी चौक सहित नगर के हर गली कोने के बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों से मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो छोटे व्यापारी आमजन को महंगे भावों में सामग्री प्रदान कर रहे है। जनता विशेषकर गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग लुटता जा रहा हैं। गरीबों की मजबूरी है कि दुकानदार जिस भाव दे खरीदकर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हो रहा है। नगर के पिपली चौराहे के आसपास किराने के व्यापारी, शांतिनगर सुलभ शौचालय के पास गांधी चौक में ऐसे दुकानदार है जो तम्बाखू उत्पादनों का स्टॉक रखे हुए है व बड़ी मात्रा में अवसर का लाभ उठाकर बेधड़क बेच रहे है। दशहरा मैदान के सामने भी घर दुकान शामिल दुकानदार के यहां आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भीड़ रहती है, जो तोल व मोल दोनों तरह से गरीबों का शोषण कर रहे है।

3 मई तक ओर चलेगी यह लूट

लॉक डाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ चुकी है और बड़े थोक व्यापारी खुश नजर आ रहे है, क्योंकि थांदला प्रशासन न केवल अनदेखी कर रहा है अपितु एक तरह से व्यवस्था बनाये रखने के लिए उन्हें परमिशन देकर चौन से बैठा है। बड़े व्यापारियों को थोक सामग्री बाहर से मंगवाने के लिए शासन द्वारा ट्रांसपोर्ट की छूट मिलने से उनकी सामग्री हर एक दिन छोड़कर आ रही है और वह मुनाफाखोरी में अपनी तिजोरियां भर रहे है। शासन प्रशासन जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री की पूर्ति हो रही है, इससे ही संतुष्ट है। जिले के अन्य स्थानों पर प्रशासन व खाद्य विभाग सक्रिय होकर भावों पर नियंत्रण रख रहा है। मुनाफाखोरों पर कार्यवाही कर रहा है। यहां तक कि दुकान शील करने तक की कार्यवाही हो रही है, परन्तु थांदला में ऐसा कुछ भी नहीं होने से व्यापारियों को लूट की खुली छूट प्रतीत हो रही है।

मेघनगर प्रशासन ने फल-सब्जी वालों का मोहल्लों से सामान छीना

माही की गूंज, मेघनगर। भूपेंद्र जैन

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गरीब वर्ग की लॉकडाउन के कारण चिंता कर रहे हैं। तो वही मेघनगर प्रशासन का तानाशाही रवैया इन दिनों चर्चा बना हुआ है। सरकार के नियम एवं शर्तों के हिसाब से फल एवं सब्जी व्यापारी घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। जिसका पास मेघनगर के एसडीएम साहब ने बकायदा जारी किया था। इसके बाद नए पास बनाने की प्रक्रिया में भी उक्त फल एवं सब्जी व्यापारियों नए पास के लिए आवेदन दे रखा है। लेकिन मंगलवार को मेघनगर प्रशासन द्वारा फल एवं सब्जी वालों को बेवजह परेशान करके उनके तराजू बांट एवं सामान जप्त कर लिया गया। जिसकी शिकायत सभी फल सब्जी व्यापारियों ने एकत्रित होकर मेघनगर विधायक एवं एसडीएम को की। अब लॉक डाउन के दौरान रोज कमा कर खाने वाले परिवारों के सामने संकट पैदा हो गया है। इस कारण छोटे व्यापारी अपने घरों पर ही थोड़ा सामान फल एवं सब्जी लाकर घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। फल-सब्जी व्यापारियों का कहना है कि हमें बार-बार इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जिस कारण फल व सब्जी बिक नहीं पाती है। जिसके चलते सब्जियों और फलों के खराब होने के कारण हमें सड़कों पर फेंकना पड़ता है। अब हमारे यहां पर खाने का संकट खड़ा हो गया है। यदि हमें फल सब्जी का व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, तो घर में खाने का संकट खड़ा हो जाएगा या फिर प्रशासन हमारे प्रत्येक घरों में एक माह का राशन उपलब्ध कराएं। मेघनगर प्रशासन का भेदभाव पूर्ण रवैया समझ के परे है। जहां रुपए 500 की मात्र चालानी कार्रवाई करके बीड़ी गुटखा ले जाने वाले लग्जरी कार को छोड़ दिया जाता हैं। वही गरीब परिवारों को बेवजह परेशान करके उनका मुंह का निवाला छीना जा रहा है। यह न्यायसंगत नहीं है।

समाधान करवाता हूं

फल-सब्जी वालों का आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। जिस पर मैं एसडीएम एवं एसडीओपी से बात कर समस्या का समाधान कराता हूं। गुटखे से भरी कार 500 रूपए में पुलिस ने चालन बनाकर छोड़ी है। पुलिस का यह रवैया ठीक नहीं है। इसके लिए मैं कलेक्टर और एसपी से बात करूंगा। **वीरसिंह भूरिया, विधायक**

वार्डों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क व सूखा नाश्ता

माही की गूंज, थांदला। महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकों ने शहर के कई वार्डों में मास्क व सूखा नाश्ता बांटा। यह कार्य विभाग की पुष्पा डोडियार के नेतृत्व में किया गया। मास्क विभाग की कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए। जिसके बाद वार्डों में बांटा गया। वार्ड 1 से लेकर 15 तक में यह कार्य किया गया। जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ता अंतिमबाला सोनी, विद्या भाभर, किरण चौधरी, ललिता डामर, ललिता चौहान आदि का सहयोग रहा। पूरे कार्य को लेकर परियोजना अधिकारी मुवेल का मार्गदर्शन रहा।

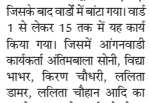

कोविड-19 संबंधी जानकारी का बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय अपराध

माही की गूंज, झाबुआ।

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी जानकारी के प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजीव चन्द्र दुबे ने आज इस आशय का आदेश जारी किये हैं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन को कोविड-19 के संबंध में तथ्यों की जाँच और यथा-स्थिति की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) द्वारा ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जायेगा, तो उसे विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध कायम कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता का संदेश

माही की गूंज, बामनिया। कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता संदेश देते हुए युवक-युवतियों ने फोटो बनाकर उसके माध्यम से ग्रामीणों अपने घरों के अंदर रहने की समझाइश दी। साथ ही सेवा कर रहे पुलिस जवानों, चिकित्सकों, नर्स और मेडिकल स्टाफका सहयोग करें। उनके कहे अनुसार उसका पालन करे ताकि हम इस बीमारी से बच सके। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए या सेनेटाइजर का प्रयोग करें। अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखें तभी हम सब मिलकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते है। कोरोना का सामना कर सकते है और सभी दूर रहकर एक दूसरे से बात करें।

मादलदा में दो माह का खाद्यान्न हुआ विलुप्त

संस्थाओं में खाद्यान्न वितरण करते समय नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिग का पालन

माही की गूंज, भामल।

जहां किराना, दूध, सब्जी से लेकर राज्य समन्वयक, भोजन कार्यक्रम परिषद भोपाल के निर्देशन में शा. माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत नगदी राशि बच्चों के बैंक खाते में डाली गई तो वही खाद्यान्न को शिक्षकों के माध्यम से घर पहुंच खाद्यान्न देने के आदेश है।

सभी को घर पहुंच उक्त अति आवश्यक सामग्री व खाद्यान्न देने के निर्देश है, वहीं सहकारी संस्थाओं में अपनी संस्था कि दुकानों से ही खाद्यान्न वितरित करना है, वह भी तीन माह का एक साथ, उक्त कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सारी व्यवस्थाएं घर पहुंच है तो, सहकारी संस्था की दुकानों से ही खाद्यान्न देने की इस व्यवस्था को पृथक क्यों किया? समझ से पर है। प्रशासन चाहता तो सहकारी संस्था भी फलिया या गांव तक पहुंचकर परिवहन के साथ यह व्यवस्था कर सकती थी, यह तय था कि इस व्यवस्था में परिवहन व्यवस्था करना आवश्यक थी।

खैर जो भी हो परंतु सहकारी संस्थाओं में खाद्यान्न वितरण करते समय कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई, न हि यहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा। शासन के निर्देशों पर अप्रैल से जून तक 3 माह का एक साथ खाद्यान्न देने के सख्त आदेश दिए हैं। जिस पर सहकारी संस्थाएं अपनी दुकानों से 3 माह का खाद्यान्न दे रही है। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत मादलदा, नगारी में भी संस्था द्वारा अप्रैल से जून तक 3 माह का खाद्यान्न दिया जा रहा है, जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गई। यहां के रहवासियों का कहना है कि, अप्रैल से 3 माह का खाद्यान्न तो संस्था दे रही है, परंतु उसके पूर्व के दो माह इन्होंने नही दुकान खोली ना ही खाद्यान्न दिया, तो हमारा पिछला 2 माह का खाद्यान्न किसको दिया व किसके गोदाम में गया। ग्रामीण कह रहे हैं कि इस 3 माह के खाद्यान्न के साथ हमें हमारा पिछला बकाया 2 माह का खाद्यान्न भी साथ में ही दिया जाए। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि मादलदा में अक्सर 1-1 2-2 माह का खाद्यान्न नहीं देते हैं और हमको मिलने वाला खाद्यान्न पप्पू सेठ के गोदाम से लेकर सहकारी संस्थाओं के भ्रष्टों की जेब में ही जा रहा है।

अंचल में कोरोना की जांच हेतु 33 सैंपल लिए

माही की गूंज, थांदला।

कोरोना महामारी को लेकर समीपस्थ कुशलगढ़ में प्रतिदिन बढ़ रही रोगियों की संख्या 59 हो गई हैं। वही एक महिला की मृत्यु हो जाने को लेकर अंचल में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का स्थानीय अमला भी मुस्तैद है।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थांदला में कोरोना जांच हेतु अभी तक कुल 33 सैंपल लिए गए हैं। जिनमें से 12 रिपोर्ट अभी नेगेटिव आ गई है तथा शेष आना बाकी है।

घर नहीं गए लैब टेक्नीशियन

स्थानीय सिविल हॉस्पिटल में पदस्थ लैब टेक्नीशियन हेमेंद्र नागर , निखिलेश नामदेव पूरी सुरक्षा के साथ सैंपल लेने में लगे हुए हैं। तो वही सैंपल लेने के बाद सीधे अपने घर नहीं जा रहे हैं।

नियमित हो रहा स्वास्थ्य परीक्षण

स्थानीय आईटीआई कॉलेज को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। जहां पर 82 लोगों को क्वॉरेंटाइन किया गया है। जिनमें 53 व्यक्ति गुजरात के हैं, तो वहीं 26 मजदूर काकनवानी के क्षेत्र के रहने वाले हैं। डॉक्टर संजय कटारा द्वारा नियमित रूप से सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बीएमओ डॉ अनिल राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अंचल में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सभी नागरिक सुरक्षा का ध्यान रखें। अपने अपने घरों पर रहे। हमारे द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं सैंपलिंग की जा रही है। वहीं क्वॉरेंटाइन सेंटर पर भी क्वॉरेंटाइन किए गए सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। जो सभी स्वस्थ हैं, किंतु सावधानी बरतना आवश्यक है। सभी अपने घरों पर रहे नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें, हाथों को सैनिटाइजर से धोते रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

लॉकडाउन में भी धंधेबाज कर रहे कपास का सौदा, प्रशासन ने की कार्रवाई

मंडी टैक्स चोरी में दो व्यापारियों से 51 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला

माही की गूंज, थांदला।

लॉकडाउन में भी अवैध धंधेबाज अपने कामों को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉक डाउन का फायदा उठाकर थांदला के दो व्यापारी मंडी टैक्स चुकाए बिना कपास की खरीदी कर अन्य जगह बेचने की तैयारी मेंथे। परंतु दो व्यापारियों को यह सौदा भारी पड़ गया। लॉकडाउन में एक ट्रक में कपास भरकर सेंधवा भेजने की तैयारी थी, किंतु लॉकडाउन में उन्हें अनुज्ञा न मिलने व मंडी प्रशासक को खबर लगते ही आला अधिकारी थांदला-लिमड़ी मार्ग स्थित व्यापारी संजय सुजानमल के गोडाउन पर कार्रवाई करने पहुंचे। किसानों से की गई खरीदी की जानकारी छुपाने और टैक्स चोरी पर व्यापारी को 5 गुना 35 हजार 800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं एक अन्य व्यापारी सुनील भागीरथ राठौड़ से 15 हजार 287 का अर्थदंड वसूला गया। दोनों व्यापारियों के यहां किसानों से क्रय किया हुआ और गोदामों में संग्रह कर रखा हुआ कपास लंबे समय से पड़ा था। लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही बंद होने से गोदाम में रखा कपास सड़ने व पीला पड़ने लग गया था यदि ई-अनुज्ञा प्राप्त न होती तो बिना अनुज्ञा के ही यह माल गंतव्य तक जा सकता था। इसके पूर्व दोनों व्यापारियों ने ट्रक में भरा पूरा कपास अपने गोडाउन में खाली कर अपनी किस्मत को कोसते नजर आए। मंडी प्रशासक ने भी दोनों व्यापारियों से 51 हजार का अर्थदंड वसूला, जो इस सीजन का सबसे बड़ा मामला है। इस संदर्भ में स्थानीय भारसाधक अधिकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन में किसी को भी आवश्यक खाद्य सामग्री के अलावा अन्य सामानों के परिवहन की छूट नहीं दी जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी खूब चली

यह खबर सोशल मीडिया पर भी खूब चली। लोग अवैध धंधेबाजों को भी कोसते नजर आए। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले में किसी ने लिखा कि व्यापारियों ने कुछ लोगों को गांधीछाप की भेंट देकर इस मामले को मात्र पैनल्टी में ही निपटवा लिया। तो वही सोशल मीडिया से उपजी जनचर्चा का विषय यह भी है कि व्यापारियों से मिले 50 हजार रुपए को 4 लोगों में बांटा गया। यह कौन थे, इसके बारें में कोई खुलासा नहीं हो सका। साथ ही इस मामले में सोशल मीडिया में मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए।

लॉकडाउन में केवल पैनल्टी क्यों?

लोगों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई पर संदेह किया जा रहा है कि लॉक डाउन में केवल पैनल्टी लगाकर व्यापारियों क्यों छोड़ दिया गया। साथ ही जब लॉक डाउन के दौरान टू व्हीलर तक पर प्रतिबंध है तो इस सौदे में शामिल गाड़ी को प्रशासन ने जब्त क्यों नहीं किया। ठीक इसी तरह इन व्यापारियों पर लॉक डाउन उल्लंघन का केस धारा 188 के तहत क्यों नहीं बनाया गया। साथ ही क्या किसी दबाव में प्रशासन ने कम माल बताकर रायल्टी में व्यापारियों को लाभ दिया गया। इस तरह के सवाल कई है पर जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर सेटिंग के चलते अवैध धंधेबाजों को बख्श दिया गया और पैनल्टी के नाम पर सरकारी खानापूर्ति कर ली गई। जिसमें प्रशासन माहिर है।

सांसद ने व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर -एसपी से की चर्चा

माही की गूंज, झाबुआ।

संपूर्ण लॉकडाउन का जिला तथा पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इस बीच जिले के लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं निर्बाध रूप से समय पर मिल सके। विशेष रूप से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मंशानुसार गरीब वर्ग के लोगों को लॉकडाउन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सांसद गुमानसिंह डामोर तथा भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में कलेक्टर प्रबल सिपाहा तथा पुलिस अधीक्षक विनीत जैन से विशेष बातचीत की। इस दौरान विभिन्ना विभागों के प्रमुख भी उपस्थित थे। सोमवार को सांसद डामोर, जिलाध्यक्ष शर्मा ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर-एसपी से संकट की इस घड़ी के बीच की जा रही व्यवस्थाओं पर चर्चा की। विशेष रूप से मुख्यमंत्री की मंशानुसार जिले में खाद्यान सामग्रियों की आपूर्ति सतत बनी रहे, इस पर चर्चा की गई। यह तय किया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन में भी किसी भी अवस्था में जिले में दैनिक उपयोगी सामग्रियों की आपूर्ति नहीं रोकी जाएगी। आवश्यक सामग्रियों की घर पहुंच सुविधा भी जारी रखी जाएगी। विशेष रूप में गरीब वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान शर्मा ने बताया कि भाजपा संगठन के माध्यम से जिलेभर में पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर राशन सामग्रियों का वितरण कार्य जारी रखेंगे। इसके साथ ही सकल व्यापारी संघ सहित कई अन्य सामाजिक संगठन, समाजसेवी, सेवाभावी सदस्य भी घर-घर जाकर गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन, राशन सामग्रियां सतत उपलब्ध करवाने में दिन-रात लगे हुए है। दोनों भाजपा नेताओं ने उनके योगदान को सराहा।

संपादकीय

लॉकडाउन की दवाई से ही बचेंगे जान और जहान

पूर्णबंदी (लॉक डाउन) को पाबंदी नहीं, दवा माना गया था। शुरू से ही यह उम्मीद बांधी गई थी कि 21 दिनों का लॉकडाउन देश की आबादी को कोरोना वायरस के कहर से बचाएगा। शायद इसमें समय की कमी रह गई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ाकर 03 मई तक कर दिया है, जो कि अब तक कुल 40 दिन का हो गया है। बेशक 21 दिनों में हम इस वायरस के प्रसार को पूरी तरह नहीं रोक सके, लेकिन यह लॉकडाउन ही था, जिसकी वजह से हालात उतने खराब नहीं हुए, जितने कि दुनिया के कुछ दूसरे देशों में आज दिख रहे हैं। जाहिर है, लॉकडाउन की इस सफलता की बात करने के साथ ही वायरस के प्रसार को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 21 दिन के लॉक डाउन की मियाद पूरी होने के बाद भी महामारी के जो खतरे पहले थे, वे अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि इसे भले ही पूर्ण लॉक डाउन कहा जा रहा था, लेकिन सभी चीजें पूरी तरह बंद करा दी गई हों, ऐसा भी नहीं था। यह भी जरूरी था कि इस दौरान घरों के भीतर लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए अति-आवश्यक सेवाओं और कारोबार आदि को बंद नहीं किया गया था। तकरीबन हर क्षेत्र में किराने के सामान, फल, सब्जियां और दवाएं वगैरह लगभग पहले की तरह ही मिलती रहीं। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य उद्योग को अगर लॉकडाउन से कुछ राहत न दी जाती, तो इनमें काफी कुछ बिगड़ सकता था। यह जरूर है कि इनके उत्पादों की बिक्री का बाजार काफी मंदा पड़ गया है। इसी तरह, दवा उद्योग को भी लॉक डाउन से राहत दी गई। इन उद्योगों और शुरू के तीन-चार दिनों में हुई कुछ गड़बड़ियों को छोड़ दें, तो यह लॉकडाउन मोटे तौर पर कामयाब रहा।

तमाम समस्याओं के बाद भी अगर करोड़ों या शायद एक अरब से ज्यादा लोगों ने न सिर्फइसकी जरूरत को समझा, बल्कि इसके अनुशासन का पालन किया, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि हमारे लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। जरूरत पड़े, तो देश के लोग वक्त की नजाकत के हिसाब से लक्ष्मण-रेखा के भीतर रहने में कोई गुरेज नहीं करते। 21 दिनों के लॉकडाउन ने एक बार फिर इस बात को समझाया है। दरअसल, कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की लड़ाई या किसी भी तरह की विपत्ति में यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है।

मंगलवार को पीएम के संबोधन के बाद लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी सभी की राय यही थी। कई राज्यों ने तो इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। एक संयोग यह भी है कि जिन राज्यों ने अभी तक यह घोषणा नहीं की, उनमें से ज्यादातर भाजपा शासन वाले राज्य थे, जो शायद पूरी तरह से पीएम मोदी के निर्णय पर ही टिके हुए थे। पीएम ने 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर राहत देने की बात कही है। हालांकि इन सभी जगहों पर कदम फूंक-फूंककर रखने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी भी लगभग पहले की तरह बना हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसे सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि हालात जैसे-जैसे सुधरेंगे, अन्य उद्योगों के लिए भी राहत दी जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि लोगों को महामारी से बचाया जाए। जब तक खतरा रहेगा, पाबंदियां जारी रखनी ही होंगी। क्योंकि लॉक डाउन की दवाई से ही जान और जहान दोनों बचेंगे।

अपने कर्तव्य निभाने का समय

रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री

भारत इस समय संकट के बेहद गंभीर दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस खौफनाक महामारी का रूप ले चुका है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान खतरे में पड़ गई है और देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक इसका कोई रामबाण इलाज नहीं मिला है। यह बड़ी चुनौती, व्यथा और चिंता का समय है। इस संकट ने पूरी मानवता को प्रभावित किया है। हालांकि कोई भी चुनौती निश्चित तौर पर एक अवसर भी प्रस्तुत करती है। हो सकता है, नए सिरे से दृढ़ संकल्प लेने और अभिनव तरीके ढूंढ़ने पर ही इस संकट से निपटना संभव हो।

महान भारतीय बाबा भीमराव आंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता होने के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हमारे देश के संविधान को एक ऐसे सामाजिक दस्तावेज के रूप में आकार दिया, जिसमें अधिकार और दायित्व के साथ-साथ सशक्तीकरण एवं समावेश भी समान रूप से महत्वपूर्ण मूल्य हैं। इन मूल्यों को स्वतंत्र भारत की सतत प्रगति के लिए अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यह भारत की अनूठी परंपरा है कि जब भी किसी चुनौती का सामना करना होता है, तो भारतवासियों की अंतर्निहित शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। हम सभी को यह याद है कि साठ के दशक में जब खाद्यान्न संकट गहराया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से हर दिन एक वक्त का भोजन छोड़ देने की अपील की थी और देश ने उनका पूरा साथ दिया था। भारत की जनता सदैव समय की कसौटी पर खरी उतरी है, बशर्ते कि देश का नेतृत्व प्रेरणादायक हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वह समय-समय पर भारत की जनता से अपील करते रहे हैं और हर बार देश ने उनका पूरा साथ दिया है। जब उन्होंने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए समर्थ लोगों से अपनी रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की, तब करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया। जब उन्होंने 'स्वच्छ भारत कार्यक्रम' शुरू किया, तब उन्होंने लोगों से इसमें स्वेच्छा से भाग लेने की अपील की। यह उनकी अपील का ही कमाल है कि पिछले साढ़े पांच वर्ष में इस काम ने व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले लिया। कई ग्राम पंचायतें अब खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं। भारत की जनता ने स्वेच्छा से स्वच्छ भारत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसा करना कर्तव्य है।

कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 'जनता कर्फ्यू' के लिए अपील की। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता से सभी डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ताली-थाली बजाने की अपील की, लोगों ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री ने पहली बार में ही पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का अभूतपूर्व कदम उठाया और भारत की जनता ने दिल से यह मान लिया कि अपने-अपने घरों तक सीमित रहना, सामाजिक दूरी बनाए रखना उनके कर्तव्य का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर जनता ने एकजुटता और उत्साह दर्शाने के लिए दीया जलाया, तरह-तरह से रोशनी की।

अधिकार और कर्तव्य हमारी सांविधानिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। यह अलग बात है कि मौलिक कर्तव्य बहुत बाद में संविधान में शामिल किए गए थे। कर्तव्य के साथ-साथ दायित्व का भी विचार हमारे संविधान की मूल विशेषता रही है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, आवागमन, निवास, इत्यादि की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में कर्तव्य का भी प्रावधान किया गया है, जिसका पालन ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे भारत की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। यदि इसका उपयोग अपेक्षित रूप से नहीं किया जाता है, तो तर्कसंगत पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करता है और ऐसा करने की मनाही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा न करना हर भारतीय का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत राज्यों को ऐसी नीति बनाने का दायित्व दिया गया है, जिसके तहत भौतिक संसाधनों का इस तरह से सर्वश्रेष्ठ वितरण हो, जिससे सभी का भला हो। अनुच्छेद 51ए में, जिसको बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों पर विशेष अध्याय शामिल है। इसकी कई महत्वपूर्ण बातों में राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा बेहतर बनाना इत्यादि शामिल हैं। मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य 55ए(जे) है, जो यह बताता है कि 'प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक क्रिया-कलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि राष्ट्र सतत रूप से उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके।'

हम इन कर्तव्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? यदि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस बड़ी चुनौती के दौरान हमारी सामूहिक इच्छा-शक्ति और कर्तव्य पालन से देश सफल होता है, तो हम अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद के अपने सामूहिक दायित्व को पूरा करेंगे। यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ राज्य सरकारों के कई प्रयासों की सराहना आज विश्व स्तर पर हो रही है।

आज हर भारतीय को स्वयं से केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि देश आपको क्या दे सकता है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि आप देश को क्या दे सकते हैं? वर्ष 2012 में अपने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने रामलीला मैदान की घटना से जुड़े एक मामले में साफकहा था कि जहां एक ओर, अधिकार और पाबंदी के बीच, तो वहीं दूसरी ओर, अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन व समानता होनी चाहिए। यदि कर्तव्य के विशेष महत्व पर विचार किए बिना ही नागरिक के अधिकार पर अनुचित या अपेक्षा से अधिक जोर दिया जाएगा, तो इससे असंतुलन की स्थिति बनेगी। अधिकार का सही स्रोत कर्तव्य है। यकीन है, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितिके दौरान हर भारतीय इसे याद रखेगा। निश्चित रूप से हम विजयी बनकर उभरेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

काम की बात

दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है।

अब राजकोषीय प्रोत्साहन जरूरी

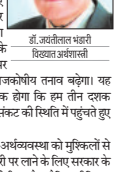

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
विख्यात अर्थशास्त्री

हाल ही में 2 अप्रैल, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन और कोरोना प्रकोप की चुनौतियों से निपटने के परिप्रेक्ष्य में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राजकोषीय घाटे के आकार में उपयुक्त वृद्धि करने की अपील की। कहा गया कि राजकोषीय दायित्व एवं प्रबंधन कानून के प्रावधानों में ढील दी जानी चाहिए। कहा गया कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3.5 प्रतिशत निर्धारित है, इसे बढ़ाकर चार प्रतिशत किया जाना उपयुक्त होगा। कहा गया कि वर्ष 2009-10 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी इसे बढ़ाकर चार फीसदी किया गया था।

जहां देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने सरकार से व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन की मांग की है, वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के द्वारा उद्योग कारोबार से संबंधित करीब 200 सीईओ के बीच किए गए जिस ऑनलाइन सर्वे का प्रकाशन पांच अप्रैल को किया गया है, उसमें उद्योग कारोबार को बचाने के लिए सरकार से राजकोषीय प्रोत्साहन के व्यापक पैकेज की जरूरत बताई गई है।

वास्तव में कोरोना प्रकोप और लॉकडाउन के बीच सरकार ने अभी जो राहत दी है वह सराहनीय है, लेकिन उद्योग कारोबार तथा कृषि व सर्विस सेक्टर में रोजगार बचाने के लिए वित्त मंत्री को और अधिक खुले हाथों से राहत देनी होगी। गौरतलब है कि 26 मार्च, को कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गरीब किसान, महिला एवं अन्य प्रभावित वर्गों के 100 करोड़ से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने का जो एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए का बहुआयामी पैकेज घोषित किया गया है वह सराहनीय है। इसी तरह 27 मार्च, को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्योग कारोबार और लोगों को वित्तीय और बैंकिंग संबंधी राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। खासतौर से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट घटाकर बड़ी राहत दी गई है। ब्याज दर में कमी का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तीन माह तक ईएमआई नहीं दिए जाने संबंधी राहत भी दी गई है। एनपीए के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक के नए फैसलों से चलन में नकदी की मात्रा बढ़ेगी। यह अनुमान है कि करीब तीन लाख करोड़ रुपए की नकदी चलन में आएगी।

निःसंदेह देश में लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों से चमकने वाले केंद्रों में निराशा का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ऐसे में दुनिया की प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना प्रकोप से इस वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को करीब नौ लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन ने देश के उद्योग कारोबार को सबसे अधिक प्रभावित किया है। देश में सबसे अधिक रोजगार सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के द्वारा दिया जाता है, देश के करीब साढ़े सात करोड़ ऐसे छोटे उद्योगों में करीब 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिली हुई है। लॉकडाउन के कारण उद्योग कारोबार के ठप होने के कारण देश के कोने-कोने में दैनिक मजदूरी करने वालों को काम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश के कुल कार्यबल में गैर संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 90 फीसदी है। साथ ही देश के कुल कार्यबल में 20 फीसदी लोग रोजाना मजदूरी प्राप्त करने वाले हैं। इन सबके कारण देश में चारों ओर रोजगार संबंधी चिंताएं और अधिक उभरकर दिखाई दे रही हैं।

निश्चित रूप से लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यदि हम अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन करें तो पाते हैं कि पिछले मार्च महीने में देश में वाहनों की बिक्री में 50 फीसदी की कमी आई। जीएसटी की प्राप्ति में 20 फीसदी की गिरावट आई। पेट्रोल और डीजल की खपत में 20 प्रतिशत की कमी आई। बिजली की खपत में 30 प्रतिशत की कमी आई। स्थिति यह है कि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में बड़ा संकुचन आ गया है।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन के कम होने और नियंत्रण घटने के बाद भी स्थितियों में सुधार धीरे-धीरे ही आएगा। संकुचित हुई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में कोई एक वर्ष का समय भी लग सकता है। निश्चित रूप से बंद पड़ी कंपनियों को दोबारा काम शुरू करने में समय लगेगा। उद्योग कारोबार के अनुकूल वातावरण के लिए भी लंबा समय लगेगा। लॉकडाउन के कारण रोजगार खोने वाले लोगों के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ने में समय लगेगा। निवेश को बढ़ाने में भी समय लगेगा। बैंकों के ऋण वितरण में रुकावटें दूर करने और बैंकों की सामान्य कार्यप्रणाली बहाल करने में भी बड़ा समय लगेगा। इन सब के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में कई उद्योग कारोबार और बड़ी कंपनियां यह अनुभव करते हुए दिखाई देंगे कि यह उनके लिए एक खोया हुआ वर्ष बनकर रह गया है।

निःसंदेह कोरोना महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के बीच उद्योग और कारोबार क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। निश्चित रूप से वर्ष 2020 में सरकार की विभिन्न प्रकार की आमदनी में कमी के कारण राजस्व के आंकड़े कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे और साथ ही कोरोना प्रकोप से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर खर्चों के कारण राजकोषीय तनाव बढ़ेगा। यह तनाव इतना अधिक होगा कि हम तीन दशक पुरानी राजकोषीय संकट की स्थिति में पहुंचते हुए दिखाई देंगे।

निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से बचाकर फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न राजकोषीय और मौद्रिक नीति का समर्थन प्रदान किया जाना जरूरी होगा। सचमुच यह समय राजकोषीय अनुशासन की चिंता करने का नहीं है। कोरोना प्रकोप के बीच दुनिया के कई देश अपनी-अपनी जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर राजकोषीय सहयोग के पैकेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अभी तक हमारे देश में राहत पैकेजों का आकार बहुत कम पांच प्रतिशत के करीब दिखाई दे रहा है।

ऐसे में देश में छोटे उद्योग कारोबार, कृषि क्षेत्र और सर्विस सेक्टर को चुनौतियों से राहत देने तथा देश में रोजगार को बचाने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार से साहसिक कदम उठाने की अपेक्षा की जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के आर्थिक प्रभाव और देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत की जरूरतों के मद्देनजर देश-दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाए जाने की जोरदार टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक सलाह

दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझाना असली ज्ञान है।

कोरोना को भारत मात देकर रहेगा

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

सोमवार को केंद्र सरकार के दफ्तरों में मंत्री लोग और बड़े अफसर दिखाई पड़े हैं, उससे आप पक्का अंदाज लगा सकते हैं कि अब यही साहस राज्यों की सरकारें भी दिखाना शुरु कर देंगी। धीरे-धीरे छोटे कर्मचारी भी दफ्तरों में आने लगेंगे। इस संबंध में मेरा पहला सुझाव तो यही है कि मध्यप्रदेश में उसके मुख्यमंत्री शिवराज चौहान अपने मंत्रिमंडल का गठन तुरंत कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं हैं। बिना भीड़-भड़क्का और धूम-धड़क्का किए हुए उनका मंत्रिमंडल भोपाल में शपथ ले सकता है।

पिछले तीन-चार हफ्तों से वे ही सरकार चलाने का बोझ अकेले उठा रहे हैं। यदि देश के सभी प्रदेशों में वहां की सरकारें सक्रिय हो जाएं तो जनता को जबर्दस्त राहत मिलेगी। जनता को यह भी अच्छा लगेगा कि वह तीन-चार हफ्ते बाद अपने डरपोक और घर-घुस्सू नेताओं के दर्शन कर सकेगी। यदि मंत्री बाहर निकलेंगे तो हजारों कार्यकर्ता भी मैदान में कूद पड़ेंगे। यह पहल कोरोना-युद्ध में भारत को विजयी बना देगी। इस समय देश के डाक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मचारी और पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। यदि करोड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता भी मैदान में आ गए तो देश की अर्थ-व्यवस्था डांवाडोल होने से बच जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि आवश्यक माल ढोनेवाले ट्रकों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उनके ड्राइवरों को तंग नहीं किया जाएगा। मालगाड़ियां चल ही रही हैं।

राज्य सरकारें अपने-अपने किसानों को फसल काटने और बेचने की सुविधा देने पर विचार कर रही हैं। यदि शहरों के कारखाने भी कुछ हद तक चालू कर दिए जाएं तो प्रवासी मजदूरों की समस्या भी सुलझेगी। जो अपने गांवों में लौटना चाहते हैं, उनका इंतजाम भी किया जाए। करोड़ों गरीबी रेखावाले लोगों को राशन और नकद रुपए सरकार ने पहुंचा दिए हैं। समाजसेवी संस्थाओं ने भी अपने खजाने खोल दिए हैं। दो लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। सैकड़ों कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। करोड़ों मुखौटे बंट रहे हैं। लोग शारीरिक दूरी बनाकर रखने में पूरी सावधानी बरत रहे हैं। कुछ प्रतिबंधों के साथ रेलें और जहाज भी चलाए जा सकते हैं। अगले दो हफ्तों में भारत कोरोना को मात देकर ही रहेगा।

बचाव के उपायों से तय होगा भविष्य

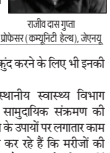

राजीव दास गुप्ता
प्रोफेसर (कम्यूनिटी हेल्थ), जेएनयू

चींन ने बेशक अपने यहां कुछ सख्त प्रतिबंधों में लोगों को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोविड-19 का कहर अब भी दुनिया पर बरस रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,700 से भी ज्यादा हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार चला गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली फिलहाल देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं, जबकि केरल ने इसे थामने में कमोबेश सफलता हासिल कर ली है। फिर भी, आबादी के आकार के लिहाज से भारत में संक्रमण-दर अभी तक कम है और देशव्यापी सामुदायिक संक्रमण के बहुत ठोस संकेत नहीं हैं। संक्रमित मरीजों के 80 फीसदी मामले देश के 62 जिलों में दर्ज किए गए हैं, और लगभग 400 जिले संक्रमण-मुक्त हैं। तीन सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन अब अंतिम चरण में है, हालांकि इस अवधि के विस्तार और इसकी प्रकृति के बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं।

खबर यह भी है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबई में सामुदायिक संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया है। वहां ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ नए रोगियों का किसी संक्रमित मरीज से सीधा संपर्क नहीं था और न ही उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है। मरने वालों में भी लगभग एक तिहाई वे लोग हैं, जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। धारावी में बीएमसी ने तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं, मगर जिस तरह से मुंबई में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं, उससे यह चिंता बढ़ गई है कि क्या भारत स्टेज-3 यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर चुका है?

अपनी नियमित मीडिया-ब्रीफिंग में विभिन्न मंत्रालयों के प्रवक्ता सामुदायिक संक्रमण को फिलहाल सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि 'ऐसे कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ, लेकिन ये मामले इतने अधिक नहीं हैं कि सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि होती हो'। वे यह भी कहते हैं कि 'सामुदायिक संक्रमण की बात हम तभी कर सकते हैं, जब संक्रमण की अबूझ वजह वाले मामलों की संख्या 20 से 30 फीसदी होगी।' पीटीआई की खबर बताती है कि इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की घोषणा के बाद तीन ऐसे मामले दिखे हैं, जिनमें मरीज के संक्रमण का कारण पता नहीं चला। एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने बीते 21 मार्च को ही तमिलनाडु के एक 20 वर्षीय युवा और पुणे की 41 वर्षीया महिला का उदाहरण देते हुए चिंता जताई थी कि क्या ये दोनों मामले देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत के संकेत हैं, क्योंकि उन दोनों मामलों में संक्रमण की वजह स्पष्ट नहीं थी?

जाहिर है, देश के अलग-अलग राज्य और उनके अलग-अलग जिले कोरोना संक्रमण के भिन्न स्टेज से गुजर रहे हैं और उसी के मुताबिक उनकी अलग-अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नए उभरते हालात के अनुसार सभी राज्य अपनी जवाबी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में, आने वाले दिनों में धारावी जैसे हॉटस्पॉट (कई कारणों से) हम बेशक देख सकते हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर सामुदायिक संक्रमण शायद ही हो। अभी देश में कई हॉटस्पॉट को चिह्नित किया गया है और वहां के लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह के हॉटस्पॉट की पहचान जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फयह पता लगाने में मदद मिलती है कि उस खास जगह पर संक्रमण किस तरह फैला, बल्कि संक्रमण के बढ़ते दायरे को थामना भी संभव होता है। कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार किस कदर खतरनाक होता है, यह दुनिया के कई देशों में देखा गया है। लिहाजा, अपने यहां स्टेज-3 से बचना ही सबसे बड़ी चुनौती है।

गौरतलब है कि हॉटस्पॉट पर सरकारी महकमे को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहां मुख्यतरू सामुदायिक समन्वय तंत्र खड़ा करने पर जोर रहता है, ताकि स्वास्थ्य, परिवहन, यात्रा, व्यापार, वित्त, सुरक्षा जैसे तमाम मोर्चों पर मुस्तैद प्रतिक्रिया दिखे। भारत में एक बड़ी चुनौती साढ़े छह लाख गांवों के घरों में सिमटी आबादी तक पहुंचना भी है। आपात स्थिति में कार्य करने वाले तंत्र का काम मामलों की जांच और संपर्कों की पहचान करना होता है। यह संक्रमण का प्रसार कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। समुदायों को उनकी सक्रिय भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना भी एक अन्य चुनौती है। प्रशासनिक तंत्र पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनकी चिंताओं को शांत करने वाले पारदर्शी, सुसंगत और सरल संदेश लगातार जारी किए जाते रहें। इस काम में स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहु-सांस्कृतिक व बहुभाषी हकीकतों को स्वीकार करने वाले संचार माध्यमों से राज्यों को इसमें मदद मिल सकती है। अफवाहों व गलत सूचनाओं के स्रोत का पता लगाने और उनकी धार कुंद करने के लिए भी इनकी मदद ली जानी चाहिए।

राज्य सरकारें और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों की तैयारी एवं सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में हालात को संभालने के उपायों पर लगातार काम कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर जगह, स्टाफऔर संसाधनों की आपूर्ति पर्याप्त रहे। इन तमाम रणनीतियों की जानकारी स्थानीय समुदायों को दी जानी चाहिए। लोगों को लगातार बताया जाना चाहिए कि इस रोग से बचाव के लिए क्या-क्या करने की जरूरत है। हालांकि साबुन से हाथ धोने को लेकर देशव्यापी अभियान चलाया गया है, लेकिन वास्तव में आज भी कई परिवारों के लिए साबुन और पानी का इंतजाम कठिन है। अच्छी बात है कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग इन स्थितियों का सामना प्रभावी रूप से कर रहे हैं। कुछ शहरों में तो सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लॉकडाउन के हालात में सभी समुदायों तक मास्क पहुंचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

निश्चय ही, सरकार के तमाम विभाग और कर्मचारी अपनी असाधारण प्रतिबद्धता के साथ इस गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। संक्रमण के हॉटस्पॉट पर सामुदायिक संगठन और स्वयंसेवक भी काफी प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। मगर फिलहाल हम एक चौराहे पर हैं। यहां से हमारी राह किधर जाएगी, यह बहुत कुछ बचाव के उपायों से ही तय होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

चाणक्य नीति

राजा की पत्नी, गुरू की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता इन सबको अपनी माता के समान मानना चाहिए। इन्हें अपनी माता के समान ही आदर-सम्मान देना चाहिए। इनके रूप सौंदर्य योवन पर आसक्त होना, इनके प्रति कुदृष्टि रखना अथवा कामुकता की भावना को स्थान देना दोष एवं पाप है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह अपनी माता के साथ अनैतिक आचरण करता है। वस्तुतः राजपत्नी, गुरू पत्नी, मित्र पत्नी और सास आदि माता के समान ही श्रद्धेय है।

व्यक्ति की पूर्णता का आधार आध्यात्मिकता ही है

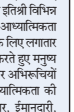

अध्यात्म का सीधा अर्थ आत्मीयता का विस्तार ही है। 'प्रेम ही परमेश्वर है' का सिद्धांत यहां अक्षरशः लागू होता है। अंतरात्मा की सघन पिपासा, प्रेम का अमृत पान करने की होती है। इसी लोभ में उसे निरंतर भटकना पड़ता है। जहां वासना होगी। वहां प्रेम का होना असंभव नहीं है। जबकि उसकी यथार्थता इतनी मार्मिक होती है कि प्रेम देनेवाला और प्रेम पानेवाला दोनों ही धन्य हो जाते है। वेदांत ने आत्मा के परिष्कृत स्तर को ही परमात्मा माना है और उसकी दृष्टि में उत्कृष्टता से भरा पूरा अंत करण ही ब्रह्मलोक है। अनेकता में समाविष्ट एकता का भाव ही ईश्वर का दर्शन है। सृष्टि का प्रत्येक सजीव और निर्जीव घटक एक-दूसरे के पूरक भी होते है। जब तक स्वतः सिद्ध सत्य, चेतना के गहन मर्मस्थल तक प्रवेश कर जाए और निरंतर इसी स्तर की अनुभूति होने लगे, तो समझना चाहिए कि अध्यात्म और जीवन का समन्वय हो गया है। पूजा की इतिश्री विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की पूर्ति के साथ ही हो जाती है, किंतु आध्यात्मिकता व्यक्ति के आंतरिक और ब्राह्य जीवन को प्रभावित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। आत्मनिर्माण के क्रम में आत्मसुधार करते हुए मनुष्य के मन में निहित आस्थाओं , मान्यताओं, आकांक्षाओं और अभिरूचियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। बहिरंग जीवन में आध्यात्मिकता की प्रतिक्रिया श्रमशीलता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सद्व्यहार, ईमानदारी, शालीनता, न्यायनिष्ठा, जनसेवा, उदारता जैसे आवरण है। ऐसे लोगों का समाजनिष्ठ, धर्मनिष्ठ कहा जा सकता है। आध्यात्मिकता को प्राचीन भाषा में ब्रह्मविद्या कहते है। यह उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य की एक परिष्कृत जीवन पद्धति है, जिसे अपनाने पर आपके भीतर संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है तथा सामाजिक जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देखा जाए, तो व्यक्ति की पूर्णता और प्रखरता का आधार आध्यात्मिकता है।

कपूत अर्थव्यवस्था के पांव और कोरोना का पालना

श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री आज (शनिवार को) मुख्यमंत्रियों से फिर वीडियो कॉनफ्रेंसिंग करेंगे।मुद्दा निश्चित ही कोरोना और लॉक डाउन रहेगा।उसके बाद हो सकता है वे किसी दिन फिर से राष्ट्र को सम्बोधित करें।वे जो कुछ भी (अगर) कहेंगे या न भी कहेंगे उसके लिए नागरिक तो पहले से तैयार हैं।जनता को पता है कि आगे क्या होना है।सवाल केवल 'कब तक' का ही बचा है।यानी 'अबकी बार,कितनी मार ?' उड़ीसा ने तो,जहाँ कोरोना के सब से कम मामले हैं और केवल एक बुजुर्ग की मौत हुई है,आगे होकर लॉक डाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।उड़ीसा के बाद तो और भी कई राज्य जुड़ गए हैं।

मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही पिछली वीडियो कॉनफ्रेंसिंग (2 अप्रैल) के बाद बीजू जनता दल के एक प्रमुख नेता पिनाकी मिश्रा ने प्रधानमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया था किरू लॉक डाउन ख़त्म नहीं किया जा रहा है पर कोरोना संकट के बाद जिंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी।

इस तरह की सोच काफी दिलासा देने वाली है कि वर्तमान संकट के ख़त्म हो जाने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।तब क्या यह मान लिया जाए कि देश की धर्म-आधारित राजनीति बदल जाएगी? नेता और अधिकारी जनता के साथ पहले और वर्तमान जैसा सुलूक नहीं करेंगे। उनका व्यवहार भी बदलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि लॉक डाउन बढ़ाने के लिए कोई मेडिकल कारण नजर नहीं आते हैं, दूसरे कोई हो सकते हैं।मसलन वैक्सीन तुरंत मिलनी नहीं है।हम जो कर सकते हैं वह यही कि टेस्टिंग की संख्या लाखों-करोड़ों में करें और संक्रमितों को स्वस्थ लोगों से अलग करें।अस्पतालों में बिस्तरों और उपकरणों को बढ़ाएं।बहुत सारी मेडिकल जरूरतों के तो अभी ऑर्डर दिए गए हैं जिनका कि उत्पादन जारी है। लॉक डाउन बढ़ाने के कोई मेडिकल कारण नहीं हैं तो फिर क्या उसे हमारी प्रशासनिक कमजोरी के साथ जोड़कर देखा जाए?भोगा हुआ अनुभव है कि किसी एक इलाके में दंगे की स्थिति में कोई एक अधिकारी तो तुरंत पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देता है और ऐसी ही स्थिति में दूसरा बस उसी इलाक़े को सील करता है।

सुझाव दिए जा रहे हैं कि संक्रमण के जो 'हॉट स्पॉट्स' हैं केवल उन्हें ही लॉक डाउन में रखें, बाक़ी विभिन्न चरणों में खोलते जाएँ।इस समय सबसे बड़ा संकट कम्यूनिटी संक्रमण को रोकने का है और उसका सम्बंध उस इलाक़े के प्रबंधन से ही है।जैसे कि ताजा चिन्ता धारावी को लेकर है।वहाँ या ऐसी और भी बस्तियों में

जब तक पूरे इलाक़े को चारों तरफसे सील कर घर-घर में टेस्टिंग नहीं कराई जाती,सजा पूरे शहर को मिलती रहेगी।जैसा कि कहा जा रहा है,कोरोना से लड़ाई अब अस्पतालों में नहीं कम्यूनिटीज में जीतना पड़ेगी।मुंबई की धारावी जैसी बस्तियों में हमारे यहाँ दस करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं।

लॉक डाउन को बढ़ाने के चिकित्सीय कारण (या बहाने) जैसे-जैसे कम होते जाएँगे,अर्थ व्यवस्था के डर उतने ही बढ़ते जाएँगे।सरकारों के पास जब सेवा-निवृत होनेवाले कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं होता तो वे सेवा-निवृत्ति की उम्र ही बढ़ा देती हैं।कपूत अर्थव्यवस्था के पाँव कोरोना के पालने में दिख रहे हैं।कोरोना संकट से निपटने में जिस तरह से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की ख़ामियां उजागर हुई हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आनेवाले संकट हमारे वित्तीय प्रबंधन की कमियाँ खोल कर रख देंगे।शासकों को तब इस तरह के आरोपों से अपना बचाव करना होगा कि वे तो केवल राजनीति और धर्म का ही अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं।अंत में यह कि लॉक डाउन को आखि़र कभी तो ख़त्म करना ही पड़ेगा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर होने के मायने

सियाराम पांड्ेय 'शांत'

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है। उनपर कुछ लिखने का इरादा लिए बैठा हूं तो उनके किस स्वरूप को याद करूं। एक छोटे आलेख में उनके जीवन की सारी बातें समाहित नहीं की जा सकतीं। उनके राजनीतिक स्वरूप की चर्चा करूं या विधिवेत्ता होने की। पहले विधिमंत्री के रूप में याद करूं या दलितों के लिए सम्मानजनक आरक्षण व्यवस्था लागू कराने वाले महानायक के रूप में। उन्हें भारतीय संविधान निर्माण में प्रभावी भूमिका के लिए याद करूं या दलितों का प्रेरणा पुरुष बनने के लिए। उनके अंदर के पत्रकार और साहित्यकार को स्मरण करूं या श्रमिकों, किसानों और महिलाओं अधिकारों के रक्षक के नाते उनका अभिनंदन करूं। एक व्यक्ति में जब ढेर सारी विशेषताओं का समावेश हो तो उसपर लिखना, उसपर कुछ भी कहना अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन भर है। यह जानता हूं इसलिए मैं उनके पत्रकार स्वरूप की चर्चा करता हूं। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपनी कलम के माध्यम से देश और समाज को, दलितों-शोषितों और वंचितों को प्रेरित करने, उनकी आत्मा को झकझोरने, उन्हें साहस से भरने का जो उपक्रम किया, उसके लिए इससे प्रभावी दूसरी कोई विधा हो भी नहीं सकती थी। वे अपने माता-पिता की चौदहवीं और अंतिम संतान थे लेकिन उनकी यशकाया के समक्ष उनके सहोदर टिक न सके। संसार उनके नाम तक नहीं जानता। आंबेडकर किसके हैं, इस पर राजनीतिक दलों के अपने दावे हो सकते हैं लेकिन वे पूरे देश के हैं। आंबेडकर होने का अपना मतलब है। ऐसा मतलब जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता।

डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर एक सफल पत्रकार थे। अखबारों के माध्यम से समाज की उन्नति का उनका सपना अकारण नहीं था। उन्हें पता था कि किसी भी आंदोलन को धार देने के लिए अखबार से बड़ा हथियार दूसरा नहीं है। यही वजह है कि शोषित एवं दलित समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने कई समाचार पत्रों एवं पांच पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं सम्पादन किया। कहना न होगा कि इनसे उनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। वे अपने समय के उन बड़े नेताओं में शुमार थे जिनका मानना था कि अखबार के सहयोग के बिना कोई भी आंदोलन पंख कटे पक्षी की मानिंद होता है।

अगर यह कहें कि डॉ. आंबेडकर दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं तो कदाचित गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी कि उन्होंने ही भारत में दलित पत्रकारिता का श्रीगणेश किया। वे दलित पत्रकारिता क्षेत्र के पहले संस्थापक, संपादक और प्रकाशक हैं। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने मराठी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी पत्र मराठी भाषा में इसलिए आरंभ किए क्योंकि महाराष्ट्र के दलित-शोषित लोग शिक्षित नहीं थे और केवल मराठी भाषा ही समझते थे। कई दशक तक उन्होंने पांच मराठी पत्रिकाओं मूकनायक (1920), जनता (1930), बहिष्कृत भारत (1927), समता (1928) एवं प्रबुद्ध भारत (1956) का संपादन किया था। इन पत्रों में बाबासाहब आम्बेडकर ने देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनकी पत्रिका श्मूकनायकश् तो अपने नाम पर सर्वथा सार्थक साबित हुई। मूक-दलितों की ही आवाज बनी। उनकी पीड़ाओं की अभिव्यक्ति में सहायक बनी। श्मूकनायकश् पत्रिका से दलितों में एक नयी चेतना जागी। उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। आम्बेडकर जब अध्ययन के लिए विलायत गए तो यह पत्र 1923 में अर्थाभाव का शिकार हो गया।

आम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक श्बहिष्कृत भारतश् निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस बीच उन्होंने अपने आलोचकों को इस पत्र के जरिए मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अपने संपादकीय में उन्होंने यहां तक लिखा था कि बाल गंगाधर तिलक अगर अछूतों के बीच पैदा होते तो श्स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हैश् की जगह उनका नारा होता- श्छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।श् भले ही इस पाक्षिक के केवल 34 अंक निकले लेकिन ये दलित चेतना और अभ्युदय के दस्तावेज हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। 29 जून 1928 को आम्बेडकर ने समता पत्र शुरू किया। यह पत्र डॉ. आम्बेडकर द्वारा समाज सुधार हेतु स्थापित संस्था समाज समता संघ का मुखपत्र था। समता पत्र बंद होने के बाद आम्बेडकर ने श्जनताश् के नाम से 24 फरवरी 1930 को पाक्षिक पत्र निकाला। 31 अक्टूबर को 1930 को यह पाक्षिक से साप्ताहिक पत्र हो गया। 1944 में, बाबासाहेब ने इसमें एक लेख लिखा-श्आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार।श् अर्थात हम शासक कौम बनेंगे। इस पत्र के माध्यम से आम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया। यह पत्र 26 साल तक चला और दलितोन्नयन की राह प्रशस्त करता रहा।

डॉ. आम्बेडकर ने 4 फरवरी 1956 को श्प्रबुद्ध भारतश् पाक्षिक शुरू किया। श्जनताश् पत्र का नाम बदलकर उन्होंने श्प्रबुद्ध भारतश् कर दिया था। यह श्अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्रश् था। बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण के बाद यह पाक्षिक बंद हुआ। इसका मतलब साफहै कि बाबा साहब जबतक जीवित रहे, उन्होंने कलम और कलमनवीसी की ज्योति जलाए रखी। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बाबासाहेब के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने श्प्रबुद्ध भारतश् को नये सिरे से शुरू करने की घोषणा की और 10 मई 2017 को उनके नेतृत्व में इसका दोबारा प्रकाशन हुआ।

भीमराव रामजी आम्बेडकर लोकप्रिय, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। विपुल प्रतिभासंपन्न थे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मरणोपरांत 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था।

जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो नौ साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे पांचवीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल-विवाह का प्रचलन था। यह और बात है कि वे बाल विवाह के प्रबल विरोधी रहे। उन्होंने भारत-पाक के बीच विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर आलोचना भी की। उनके शब्दों में, बहुविवाह और दूसरी औरत रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किये जा सकते जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुःख के स्रोत हैं। जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। वे पहले भारतीय थे जिसने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की।

महाड शहर में दलितों को चवहार तालाब से पानी लेने के अधिकार दिलाने का मामला हो या 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाने का, उन्होंने इन आंदोलनों में जोरदार ढंग से हिस्सा लिया। मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था उन्मूलन के प्रति कथित उदासीनता के भी वे कटु आलोचक रहे। इस क्रम में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने दलितों के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही हस्तक्षेप न हो। लंदन में 8 अगस्त, 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आम्बेडकर ने अपने विचार दुनिया के सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा था कि शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। 1932 में ब्रिटिशों ने आम्बेडकर के विचारों के साथ सहमति जताते हुए दलितों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्ग को दो वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से उन्हें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलित वोटों से ही चुना जाना था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने पूना की येरवडा जेल में मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तब आम्बेडकर ने कहा था कि यदि गांधीजी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखते तो अच्छा होता लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं हैं। उनकी जान बचाने के लिए वह दलित हितों का त्याग नहीं कर सकते।

देश में बढ़ते दबाव के मद्देनजर आम्बेडकर को 24 सितम्बर 1932 को येरवडा जाना और गांधीजी के साथ पूना पैक्ट करना पड़ा। इस दौरान आम्बेडकर ने दलितों को कम्यूनल अवॉर्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की। लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा कर 148 करवा ली। इसके साथ ही दलितों के लिए देश के हर राज्य में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। वे ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ हुए जो पैदा तो हुए हिंदू धर्म में लेकिन निर्वाण प्राप्त किया बौद्ध धर्म में रहते हुए। वे चाहते तो इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते थे लेकिन अर्थ के प्रलोभन के आधार पर झुकने की बजाय उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया।

वे बड़े अर्थशास्त्री थे। उनके विचारों के आधार पर ही देश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये विचार उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि शिक्षा ही हर समस्या के समाधान की कुंजी है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश बाद में दिया, पहले उसे अपने जीवन में उतारा। सही मायने में वे दलित चेतना के महानायक थे। उनमें पहली बार जागरुकता और उठ खड़े होने का भाव डॉक्टर आंबेडकर ने भरा। भारतीय संविधान की सफल ड्रॉफ्टिंग कर उन्होंने राष्ट्र की जो सेवा की है, उन उपकारों का यह देश हमेशा ऋणी रहेगा। डॉ. आंबेडकर भले ही अपने पार्थिव शरीर से हमारे बीच नहीं हैं लेकिन शिक्षा, एकजुटता और संघर्ष करने का उनका मंत्र चिरकाल तक मानव सभ्यता को दशा-दिशा देता रहेगा। उपेक्षित और शोषित समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा।

मानवता के दुश्मन हैं 'लॉक डाउन' की धज्जियाँ उड़ाने वाले

निर्मल रानी, लेखिका

इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस के चलते विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है। जब तक इस लाईलाज महामारी का कोई सटीक ईलाज नहीं निकल आता तब तक स्वयं को इस महामारी से बचाए रखना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच समझा जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना प्रभावित दुनिया के अधिकांश देश इस समय तालाबन्दी या सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने पर अधिक जोर दे रहे हैं। इतिहास में पहली बार भारत सहित विश्व के कई देशों में , अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख देने वाले लॉकडाउन जैसे सख्त कदम इसी मकसद के तहत उठाये गये हैं। सवाल यह है कि जब देश की सरकारें देश की अर्थव्यवस्था से अधिक महत्व देशवासियों के जीवन की रक्षा को दे रही हों, ऐसे में यदि कुछ लोग या कोई संगठन अथवा कोई समूह सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन की नीति की धज्जियाँ उड़ाए और इन्हें धत्ता बताते हुए धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करे,जलसा,जुलूस निकाले अथवा सड़कों पर सामूहिक रूप से उतर कर नाच गाना,हुल्लड़ बाजी करे या आतिशबाजी चलाए अथवा उत्सव मनाये तो समाज के ऐसे लोग निश्चित रूप से माफी के कतई हकदार नहीं हैं।

परन्तु दुर्भाग्यवश सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर कुछ लोग जो स्वयं को तथाकथित धार्मिक,राष्ट्रवादी यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्त्ता व मोदी समर्थक होने का ढोंग करते हैं वे भी लॉक डाउन की धज्जियाँ उड़ाने में व्यस्त हैं। पिछले दिनों दिल्ली स्थित निजामुद्दीन जैसी अत्यंत भीड़-भाड़ वाली जगह से बड़ी संख्या में जमाअत के सदस्य पाए गए। खबरों केअनुसार इनमें दर्जनों जमाअती विदेशी नागरिक थे और इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव भी बताए जा रहे हैं। इनमें कई लोगों के कोरोना के कारण मरने की भी खबर है। देश के विभिन्न धर्मों के और भी कई धर्मस्थलों से इसी तरह की भीड़ इकट्ठी होने की खबरें मिलीं। ऐसे अधिकांश स्थानों से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि चूँकि यह लोग लॉक डाउन की घोषणा से पहले से यहाँ आए हुए थे और लॉक डाउन की घोषणाके बाद अपने अपने गंतव्यों तक नहीं जा सके इसलिए यहाँ पनाह लेने के सिवा इनके पास कोई चारा भी नहीं था। इनमें जमाअत के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉक डाउन की घोषणा के बाद दिल्ली के कई संबंधित अधिकारियों को पूरी स्थिति से लिखित रूप से अवगत कराते हुए मरकज में रह रहे लोगों की जानकारी भी दी थी तथा इन्हें यहाँ से निकालने के लिए बसों की भी मांग की थी । परन्तु दिल्ली सरकार की तरफसे कोई सहायता नहीं की गयी। परिणाम स्वरूप इस प्रशासनिक अनदेखी ने महामारी को और अधिक हवा देने का काम किया। अब यह गलती जमाअत प्रमुख की है या दिल्ली के अधिकारियों की,निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। परन्तु यह तो तय है कि इस लापरवाही ने मानवता को भरी क्षति पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच दो बार देश की जनता को संबोधित भी किया। सर्वप्रथम उन्होंने 22 मार्च को देश में जनता-कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की तथा जनता से आह्वान किया कि उसी दिन 5 बजे सायंकाल अपने घर के दरवाजे पर या बालकनी-खिड़कियों के सामने खड़े होकर पांच मिनट तक ताली या थाली बजा कर उन लोगों के प्रति कृतज्ञता जताएं, जो हमें कोरोना से बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, पहला संकल्प और दूसरा संयम। परन्तु 22 मार्च को 5 बजे शाम जब प्रधानमंत्री के आवाह्न पर देश 5 मिनट ताली व थाली बजा चुका उसके बाद देश में अनेक स्थानों पर यही ताली व थाली पीटने वाले लोग जुलूसों के शक्ल में ताली,थाली,घंटी,घंटा व शंख आदि बजाते हुए सड़कों पर उतर आए। बेशक यह लोग मोदी की जयजयकार कर रहे थे परन्तु इन्होंने प्रधानमंत्री के कहने के विपरीत अपना संयम भी खोया और जनता कर्फ्यू का उल्लंघन भी किया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ाईं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 5 अप्रैल को देशवासियों से रात नौ बजे नौ मिनट के लिए दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया। पीएम मोदी की इस अपील को भी देश का समर्थन मिला। परन्तु प्रधानमंत्री ने तो 9 मिनट के लिए केवल दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया था। परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इन नौ मिनटों के दौरान और 9 मिनट के बाद जो कुछ देखने को मिला वह बेहद शर्मनाक और प्रधानमंत्री के आवाह्न की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ने वाला दृश्य था। देश के कई इलाकों में इस दौरान जयश्री राम के नारे लगाए गए और बड़े अतिशबाजियाँ जलाकर प्रदूषण फैलाया गया। यह किसी की समझ में नहीं आया कि आतिशबाजी चलाकर स्वयं को मोदी समर्थक बताने व जताने वालों ने इस महामारी का स्वागत किया या इससे होने वाली विश्वव्यापी मानवीय क्षति पर जश्न या उत्सव मनाया। कई जगह गोलियां फायरिंग कर न जाने क्या सन्देश दिया गया। प्रधानमंत्री के द्वीप जलने का अर्थ यदि अंधकार को चुनौती देना था तो आतिशबाजी और गोलियां चलाने का अर्थ क्या था ? वह भी जुलूस की शक्ल में जोकि सरे आम लॉक डाऊन व सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना थी ? इस संबंध में एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि लॉक डाउन के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में पूरे देश में आतिशबाजी की व्यवस्था कैसे और कहाँ से की गयी ?

5 अप्रैल को ही पटना में इसी आतिशबाजी जश्न के दौरान एक डेयरी में भीषण आग लग गयी। कई बेजुबान गाएं व भैंसें इस आग की चपेट में आ गईं । कई बेजुबान मवेशी बुरी तरह झुलस गए। आग की लपटें पूरी डेयरी को स्वाहा कर आस पास के घरों को भी लीलने वाली थीं कि आस-पास के घरों को खाली करवाया गया तथा दमकल की गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर देर रात आग पर काबू पाया। जरा सोचिये स्वयं को सत्ता व मोदी समर्थक बताने वाले यह लोग जो हजारों की तादाद में इकठ्ठा होकर हुड़दंग मचा रहे थे और श्लॉक डाउनश् की धज्जियाँ उड़ा रहे थे इनका अपराध क्या किसी से कम है ? इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा पार्टी के एक विधान पार्षद के यहाँ आयोजित एक विवाह समारोह में शरीक हुए, जहां कम से कम 2 हजार मेहमान हिस्सा ले रहे थे। कोरोना महामारी के मद्देनजर कर्नाटक सरकार में भी लॉक डाउन है तथा राज्य सरकार ने अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जब मुख्यमंत्री स्वयं अपने ही आदेश का उल्लंघन करेंगे तो वह जनता से लॉक डाउनपर अमल करने की उम्मीद कैसे करेंगे ? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भी भाजपा के एक विधायक दादाराव केचे ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए गत 5 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विधायक ने सैकड़ों लोगों को अपने घर पर इकठ्ठा किया। लॉक डाउन व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाने वाले चाहे वे किसी भी धर्म या संगठन अथवा विचारधारा के हों दरअसल वे सभी मानवता के दुश्मन हैं।और इन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

जीवन की सुरक्षा से बड़ी नहीं अर्थव्यवस्था

प्रमोद भार्गव

संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाने की आशंका जताई है। उसका अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर जीडीपी घटकर 4.8 फीसदी रह सकती है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के ही श्रमिक संस्थान श्अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनश् ने भारत में 40 करोड़ लोगों के गरीबी के दायरे में आ जाने की चिंता जताई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी संस्थाएं भी इन्हीं से मिलती-जुलती आशंकाएं जता रही हैं। हालांकि इनमें कोई नहीं बात नहीं है। भारत शहरों से ग्रामों की ओर पलायन करने वाले लोगों को सड़कों पर देख चुका है। देशबंदी की घोषणा के बाद पलायन का यह आकार सड़कों पर दिखेगा, इसका अंदाजा पंचवर्षीय योजना बनाने वाले नेताओं और नौकरशाहों को भी नहीं था। बावजूद कोविड-19 महामारी से भारत ही नहीं उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, जिनमें कोरोना के चलते लॉकडाउन के हालात बने हैं। क्योंकि इस विकट स्थिति में घरेलू काम-धंधों से लेकर सीमापार व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और द्विपक्षीय संधियों के तहत होने वाले सौदे भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा इसलिए प्रभावित नहीं होगी क्योंकि एक तो हमारे पास इस महामारी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व है, दूसरे हमारी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और खेती-किसानी से होती है।

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 40 से 45 करोड़ है। इन्हीं में से करीब 20 प्रतिशत यानी नौ करोड़ लोग सड़कों पर थे। इस मौजूदगी से साफहो गया कि असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वैसे भी भारत में 90 प्रतिशत कर्मशील आबादी असंगठित क्षेत्र में है। इसी में से 40 करोड़ लोगों के गरीब हो जाने की चिंता एजेंसियों ने जताई है। जबकि इन्हीं एजेंसियों ने सितंबर 2018 में कहा था कि नरेंद्र मोदी की उचित आर्थिक नीतियों के चलते 2016 में 27 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आ गए हैं। यह उपलब्धि कोरोना प्रकोप ने संकट में डाल दी है। इस स्थिति को मोदी समेत हमारे सभी मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों सहित केंद्र शासित प्रांतों को आपात आर्थिक सहायता के रूप में 15000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की न केवल घोषणा की बल्कि इसकी पहली किश्त जारी भी कर दी। हालांकि जो आर्थिक क्षति महामारी से होगी उसकी पूर्ति के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि हमें वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थाई तौर पर पुख्ता बनाए रखना है तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण पर सिलसिलेवार विराम लगाते हुए ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने के ठोस उपाय करने होंगे? इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन होता है, वह थमेगा और नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ और बर्फसे ढंकी जो प्राकृतिक संपदा है, वे सुरक्षित बनी रहेंगी। मानव स्वास्थ्य भी सही रहेगा, जैसा हम आज लॉकडाउन के चलते अनुभव कर रहे हैं।

आर्थिक उदारीकरण ने अकल्पनीय औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। बहुराष्ट्रीय कंनियों के दबाव में ऐसी नीतियां बनाई गई, जिससे ग्राम एवं कस्बों में स्थित उद्योगों की कमर टूट गई। राजनीतिक मजबूरी अथवा अदूरदर्शिता के चलते 2007 में देशी-विदेशी कंपनियों को लघु-उद्योगों में 24 प्रतिशत निवेश की बाध्यता समाप्त कर दी गई थी। इस उपाय को लघु उद्योग क्षेत्र में प्राण डालने का बहाना बताया गया था, लेकिन देखते-देखते लघु व मंझोले उद्योग डूबते चले गए। इसी हश्र की आशंका थी। दरअसल प्रकृति के बेहिसाब दोहन से करोड़ों-अरबों के वारे-न्यारे करने वाली कंपनियां लघु-उद्योगों के व्यवसाय में इसलिए नहीं जुड़ीं क्योंकि इनमें अकूत धन कमाना संभव नहीं है। नतीजतन देशी-विदेशी उद्योगपतियों ने इन्हें व्यावसायिक दृष्टि से कभी लाभदायी नहीं माना। गोया, न तो लघु उद्योगों में निवेश हुआ और न ही इनकी संख्या बढ़ी। हां, एक समय लघु उद्योगों के लिए जो एक हजार के करीब उत्पाद आरक्षित थे, उन्हें घटाकर सवा सौ कर दिया गया। शेष उत्पादों के निर्माण व वितरण की छूट कंपनियों को दे गई। जबकि देश में उदारीकरण की नीतियां लागू होने से पहले, बड़ी संख्या में लघु उद्योग, बड़े और मंझोले उद्योगों की सहायक इकाइयों के रूप में काम करते थे और अपने उत्पादों को इन्हीं कंपनियों को बेच देते थे। कंपनियों के हित में नीतियां बना दिए जाने के कारण, इन लघु उद्योगों की भूमिका घटती चली गई और बची-खुची कसर चीन और दूसरे देशों से सस्ते उत्पाद आयात करने की प्रक्रिया ने खत्म कर दी। वैश्वीकरण का यह ऐसा दुखद पहलू था, जिसने ग्राम व छोटे शहरों में स्थित कामगारों को बेरोजगार किया और युवा होते लोगों को महानगरों की ओर रोजगार के लिए विवश किया।

आर्थिक उदारीकरण के बाद दुनिया तेजी से भूमंडलीय गांव में बदलती चली गई। यह तेजी से इसलिए विकसित हुई क्योंकि वैश्विक व्यापारीकरण के लिए राष्ट्र-राज्य के नियमों में ढील देते हुए वन व खनिज संपदाओं के दोहन की छूट दे दी गई। इस कारण औद्योगिकीकरण व शहरीकरण तो बढ़ा लेकिन परिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता चला गया। ग्रामों से शहरों की ओर पलायन बड़ा। नदियां दुषित हुईं। विकास के लिए तालाब नष्ट किए गए। राजमार्गों, बड़े बांधों, औद्योगिक इकाइयों और शहरीकरण के लिए लाखों-करोड़ों पेड़ काट दिए गए। नतीजतन वायु प्रदूषण बढ़ा और इसी अनुपात में बीमारियां बढ़ीं। परंतु अब कोरोना संकट ने हालात पलटने की स्थितियों का निर्माण किया है। सभी तरह के आवागमन के साधनों पर ब्रेक लग गया है। अंतराष्ट्रीय व अंतरराज्जीय सीमाएं प्रतिबंधित हैं। सामाजिक आचरण में दूरी अनिवार्य हो गई है। कोरोना के समक्ष चिकित्सा विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिन यूरोपीय वैश्विक महाशक्तियों के उत्पाद खपाने के लिए आर्थिक उदारीकरण की रचना की गई थी, वे शक्तियां इस अदृश्य महामारी के सामने नतमस्तक हैं। सबसे बुरा हाल इटली, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ईरान का हुआ है। जो चिकित्सक हर मर्ज की दवा देने का दावा करते थे, वे मनुष्य को मनुष्य से दूर रहने और प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए फल, सब्जी व दाल-रोटी खाने की सलाह दे रहे हैं। अलबत्ता इस देशबंदी का अब यह सकारात्मक पहलू देखने में आ रहा है कि लुधियाना से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी हैं। गंगा और यमुना जैसी दूषित नदियों का पानी निर्मल दिखाई देने लगा है। वायु प्रदूषण दूर हो जाने से हर व्यक्ति स्वस्थ्य अनुभव कर रहा है।

कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं, जो इस महामारी के चलते सामने आई देशबंदी को आर्थिक समस्या के रूप में देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था में नौ लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। जबकि यह संकट अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा मानव-स्वास्थ्य और गरीब व वंचितों की रोजी-रोटी से जुड़ा है। बहरहाल, अर्थ की जो भी हानि हो, सकल घरेलू दर में जो भी गिरावट आए, इस वैश्विक संकट के चलते देश को निवेश के भारी संकट से गुजरना होगा? बैंकों में औद्योगिक कर्जों की वापसी असंभव है। साफहै अर्थ-चक्र में जरूरी गतिशीलता का बने रहना मुश्किल है। यह स्थिति दर्शाती है कि देश भीषण अर्थ-संकट से घिर जाएगा? लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीपति देशों की तरह केवल औद्योगिक घरानों पर आश्रित नहीं है। इसके उलट यह खेती-किसानी, व्यापारिक लेन-देन और एमएसएमई मसलन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से ही चलती है। इससे पारंपरिक रूप से कुशल और अकुशल व्यवसायी जुड़े हैं। दूध और दूध से बने सह-उत्पाद इसी दायरे में आते हैं। अकेले दूध के व्यापार से सात करोड़ से भी ज्यादा पशुपालक जुड़े हैं। देशज अर्थव्यवस्था में इसकी आज भी 45 प्रतिशत की भागीदारी है। यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जिन लघु उद्योगों से जुड़े उत्पादों के निर्माण की छूट दी गई है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए तो लघु उद्योगों को तो ऊर्जा मिलेगी ही, उन अकुशल लोगों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेंगे, जो शहरों में सस्ते श्रमिक रहते हुए देशबंदी के चलते घर लौटने को मजबूर हुए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

न्यूज ब्रीफ

कोरोना संक्रमित की मृत्यु के बाद परिवार के छः सदस्यों के लिए सैंपल

माही की गूंज, झिरन्या। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदमों की आहट झिरन्या में भी महसूस की जाने लगी है। खरगोन व्याह भीकनगांव के रास्ते झिरन्या पहुंचे कोरोना संक्रमित शेख रफीक ने विगत दिनों एम वाय हॉस्पिटल इंदौर में अंतिम सांस ली थी। इस खबर के बाद झिरन्या में दहशत उत्पन्न हो गई। प्रशासनिक अमला ताबड़तोड़ कार्यवाही में जुट गया। इसी क्रम में 11 अप्रैल को कार्यपालिक दंडाधिकारी ने मृतक के भाई के घर पर नोटिस चस्पा कर परिवार के सभी सदस्यों को 30 अप्रैल तक अपने घर में खुद को आयसोलेट रखने की हिदायत दी थी। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने परिवार के आठ में से छः सदस्यों के सैम्पल लिए। सैम्पल की रिपोर्ट आने के बाद भी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी।

जिला और जनपद पंचायतों में प्रशासक नियुक्त

माही की गूंज, खरगोन। राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किए गए है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप पूर्व में प्रशासकीय समितियों के गठन के निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायतों के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जिला पंचायतों के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

सीएमएचओ की तरह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाताओं को भी अधिकार

माही की गूंज, खरगोन। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत नोवल कोरोना, कोविड-19 को संक्रामक रोग तथा धारा 51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए घोषित किया गया है। समस्त अधिकार समस्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह.मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को दिए गए है। इसके अतिरिक्त धारा 3 की उपधारा 9 के अंतर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेट एजेंसीक्यूटिव अथॉरिटी अधिसूचित किए गए है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा 71, 2 प्रावधानित समस्त अधिकार उपरोक्त अधिकारियों के साथ ही राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को भी दिए गए है।

नाकाबन्दी कर रहे युवक पर लट्ठ से किया हमला

माही की गूंज, बमनाला। देश मे फैले जानलेवा कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री मोदी घरों से बाहर नही निकलने की अपील कर रहे है तो दूसरी तरफरोजाना बिना वजह सड़क पर घूमने वाले लोग लॉक डाउन का खुला उलंघन कर रहे है और कभी डॉक्टरों तो कभी पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे है। आज बमनाला में भी ऐसा ही वाकया घटा है इस बार गांव की सीमा पर कोरोना वायरस से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से नाकेबंदी में तैनात युवकों से गांव का ही एक युवक अजय पिता भगवान सिंह मंडलोई निवासी बादशाह मोहल्ला बमनाला जो बिना वजह से तीन दिनों से रोड पर घूम रहा था उसे समझाना नाकेबंदी में तैनात युवक को भारी पड़ गया, आरोपी अजय गाली गलौच करते हुए नाकेबंदी कर रहे युवक देवराम पिता शिवराम राठौड़ के ऊपर हमला कर दिया जिससे उसके हाथ पर चोट आई है। जिसकी सूचना नाकेबंदी कर रहे दूसरे युवक द्वारा 100 डायल को दी गयी सूचना मिलने पर 100 डायल वाहन मौके पर पहुंचा और आरोपी युवक को लेकर थाने पहुंचा जिसके बाद एएसआई रमेश पँवार ने आरोपी के विरुद्ध शांतिभंग की धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

नगरीय निकायों में कर्फ्यू के साथ लॉक डाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी

माही की गूंज, खरगोन।

कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्यहित के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने 14 अप्रैल दोपहर 1 बजे से 20 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक तत्काल प्रभाव से जिले की सभी 8 नगर पालिका व नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश लागू कर दिए है। किसी भी व्यक्ति को जिले की नगर सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों, मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने या यातायात के कोई भी साधन का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। कर्फ्यू के आदेश में नगरीय निकायों में निवासरत रहवासियों को निर्देश दिए कि वे अपने घरों में ही रहे, ताकि सोशल डिस्टेंडिंग का पालन किया जा सके। कलेक्टर श्री डाड ने कर्फ्यू के आदेश में छूट के भी प्रावधान किए है। कर्फ्यू के आदेश में छूट का प्रावधान केवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लगे अमले के लिए किए गए है।

छूट के प्रावधान इन पर होंगे लागू

कर्फ्यू के आदेश में कलेक्टर श्री डाड ने व्यवस्थाओं व सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगे व्यक्तियों को प्रदान की है। उनमें शासकीय अथवा निजी चिकित्सा संस्था एवं उनमें कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी व अन्य अमले, पुलिस बल, नगर पालिका, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर, किसी तरह की एंबुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा शासकीय कार्य संपादित करने वाले नियुक्त अधिकारी व कर्मचारीगण, आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को ही छूट प्रदाय की गई है।

कर्फ्यू के बाद की स्थितियों पर नियंत्रण के लिए बैठक

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंगलवार को समूह के सभी सदस्यों ने कर्फ्यू लगाने की सहमति जताई। समूह के सहमति के पश्चात कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने कर्फ्यू के आदेश जारी किए। स्वामी विवेकानंद सभागृह में आयोजित हुई इस बैठक में कर्फ्यू के बाद बाहर निकलने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण करने तथा उनके साथ सख्ती का बर्ताव करते हुए उन पर कार्यवाही करने पर चर्चा करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर जोर दिया। इस संबंध में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने नगर पालिका सीएमओ तथा राजस्व अमले को निर्देश दिए कि दलों का गठन किया जाए तथा उन क्षेत्रों पर न सिर्फनिगरानी रखे, बल्कि दल भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें। इसमें जेल वाहन तथा अस्थाई बनाए गए कारागार पर रखे गए अमले को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स पर लगने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रण करने पर भी मंथन किया गया। बैठक में क्षेत्रीय विधायक श्री रवि जोशी, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री डीएस रणदा, नपा सीएमओ निशिकांत शुक्ला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अजय जैन, सचिव डॉ. निशांत महाजन, सामाजिक कार्यकर्ता ओमजी पाटीदार, अलताफ आजाद रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉ. पालीवाल उपस्थित रहे।

3 मई तक बंद रहेंगे सभी सिनेमा घर

राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे। पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था।

20 अप्रैल तक बंद रहेंगी सभी मदिरा-मांस की दुकानें

प्रदेश में संचालित सभी मदिरा-मांस की दुकानें 20 अप्रैल तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के विस्तार पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत यह कार्यवाही की है।

मालयान को नहीं रोकने के संबंध में जारी किए आदेश

कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन में माल यानों को प्रदेश में ना रोके जाने के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किए है। जारी आदेश में विभाग के आयुक्त की मधु कुमार ने बताया कि प्रदेश में कहीं भी कोई मालयान, चाहे वह भरा हो या खाली हो, रोका नहीं जाएगा। यदि किसी मालयान को रोका जाता है, तो इसकी सूचना डायल-100 पर दे, ताकि मालयान को तत्काल छोड़ने की कार्यवाही की जा सके।

खरगोन में निकला फ्लेग मार्च

माही की गूंज, खरगोन।

कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्यहित के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए है। इसी के अंतर्गत मंगलवार को पुलिस बल द्वारा शहर में फ्लेग मार्च निकाला गया। यह फ्लेग मार्च स्थानीय पुलिस थाना परिसर से प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचा। फ्लेग मार्च में कलेक्टर श्री डाड, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय, एएसपी श्री जितेंद्रसिंह पंवार, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, एसडीओपी ग्लेडविन ई-कार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहें।

बाईक पर क्रूरता पूर्व ले जाए जा रहे 10 मुर्गे, दो आरोपियों सहित गाड़ी जप्त

माही की गूंज, बड़वानी।

थाना बड़वानी पुलिस ने दो व्यक्तियों को एक्टीवा मोटर सायकल पर 10 सफेद बायलर मुर्गे क्रुरता पूर्वक बांधकर ले जाते हुए पकड़ा जिनके विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे बड़वानी शहर में कलेक्टर द्वारा पूर्ण लॉकडाउन करने लिए धारा 144 लागु की गई है। जो पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने कस्बा बड़वानी में पूर्ण रुप से लाक डाऊन का पालन करवाने के लिये थाना प्रभारी टीआई राजेश यादव को निर्देश दिए गए। जिस पर कोतवाली टीआई राजेश यादव ने कस्बे में सभी मुख्य स्थानों पर पाइंट लगाकर आने-जाने वालों को चौक करने के निर्देश दिए तथा स्वयं सम्पूर्ण कस्बे का भ्रमण कर लोगों का लॉकडाउन का पालन करवा रहे है। सोमवार को रात करीब 09 बजे टीआई राजेश यादव फोर्स व निर्भया मोबाईल को साथ लेकर कस्बे में घूम रहे थे। तभी टीआई राजेश यादव को ग्राम बड़गांव के सरपंच द्वारा सूचना दी गई की दो व्यक्ति एक्टीवा मोटर सायकल पर 10 मुर्गे बांधकर बंधान तरफ से ला रहे थे, जिन्हें हमने पकड़ा है। तो पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों व्यक्तियों के नाम पते पुछे तो जुनेद पिता मेहमुद अजहर व साबाद उर्फ सोनु पिता इस्माईल कुरैशी उम 19 वर्ष दोनों निवासी मदिना नगर बड़वानी के होना बताया। जिनकी एक्टीवा मोटर सायकल पर 10 बायलर के मुर्गे क्रुरता पूर्वक बंधे हुए मोटर सायकल सहित दोनों आरोपियों को थाने पर लाकर मुर्गे व मोटर सायकल जप्त की गई तथा दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी टीआई राजेश यादव ने बताया कि लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़वानी पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।

बलवाड़ा बैंक ऑफ इंडिया के बहार लगी लंबी कतार लाइन आधे गांव तक लगी है लाइन नहीं इन लोगों के लिए कोई टेंट व्यवस्था है बलवाड़ा में इस तरह की पब्लिक देख कर तो लगता है कि बलवाड़ा में लॉक डाउन ही नहीं है।

एसएमएस प्राप्त किसानों से ही होगी खरीदी

- सोशल डिस्टेंडिंग के लिए बढ़ाएं 21 केंद्र

माही की गूंज, खरगोन। रबी विपणन वर्ष 2020-21 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन आज बुधवार से प्रारंभ होगा। कोविड-19 के लिए पूर्व में स्वास्थ्य विभाग व शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। गेहूं उपार्जन में किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंडिंग प्रभावित न हो, इसके लिए 21 केंद्र बढ़ाए गए है। इस तरह जिले में अब कुल 91 केंद्रों पर समर्थन मूल्य 1925 रूपए प्रति क्विंटल पर खरीदी की जाएगी। सहायक खाद्य आपूर्ति भारतसिंह जमरे ने बताया कि जिन किसानों को मोबाईल पर मेसेज भेजे जाएंगे, वे ही खरीदी केंद्रों तक आएं, अन्यथा लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी। जिले में कुल 91 खरीदी केंद्रों में 32 गोदाम स्तरीय, 56 संस्था (सोसायटी) स्तरीय व 3 मंडी स्तरीय गोदाम बनाए गए है। जिले में कुल 39995 किसानों का पंजीयन हुआ है।

माही की गूंज, खण्डवा।

खण्डवा में नगर निगम की सेंट्रलाइज्ड किचिन में अत्याधुनिक मशीन से रोटी और सब्जी तैयार हो रही हैं। सुबह 8 हजार से अधिक लोगों को रोटी सब्जी और शाम को 22 क्विंटल खिचड़ी तैयार कर वाहनों से हर गली मोहल्ले में जाकर वितरित की जा रही है। जिससे लॉक डाउन से परेशान लोगों को काफी राहत मिल रही है।

फल सब्जी के लिए मशक्कत तो कच्ची शराब का धड़ल्ले से हो रहा विक्रय

माही की गूंज, झिरन्या। कोरोना से सर्वाधिक पीड़ित राज्य महाराष्ट्र की सीमा पर बसे आदिवासी विकास खंड झिरन्या में लॉकडाउन के चलते पिछले तीन सप्ताह से सभी तरह की दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद है। आमजनों को रोजमर्रा की वस्तुओं के अलावा फल एवं सब्जियों के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस एवं आबकारी विभाग की अनदेखी के नतीजेस्वरूप अंचल के अमूमन अधिकांश ग्रामों में कच्ची शराब बनाने व बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। अप्रमाणित एवं अमानक तरीके से निर्मित हो रही शराब आने वाले दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना को पीले चावल न दे दे।

डॉ.भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई

माही की गूंज, बड़वाह। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी की 129 वी जयंती सामाजिक विचार मंच व भाजपा अजा मोर्चा बड़वाह के द्वारा सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई ।भाजपा नेता व मंच संयोजक एन.एस. सोलंकी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते देश मे लाकडाउन चल रहा है। शासन- प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए प्रातः 11 बजे सामाजिक विचार मंच व अजा मोर्चे के सदस्यों के द्वारा अपने निवास पर ही डॉ.भीमराव अंबेडकर जी की 129 वी जयंती उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण कर सादगीपूर्ण तरीके मनाई गई ।शाम 7.30 पर अपने घरों में दीपक जलाकर बाबा साहेब को श्रद्धाभाव के साथ नमन किया ।इस अवसर पर सदस्य साथी पी.एन. कांदौडे ,पी एल भालसे,टी सी गोखले रमेशचंद मंडलोई ,दिनेश कोठिया ,एच.आर.कड़ोले,उमेश ठाकुर,रमेश सावले ,अनिल सावले,आर.एस. चौहान, दिनेश भगत,शंकर सावले,टी आर भार्गव,बी आर अवचरे,बी एस खांडेकर,बी एल सावले,राहुल वर्मा विजय वर्मा,नंदू ठेकेदार ,रेवाराम टैगोर ,गोपाल कोचले,एस.आर. भालेराव महेश भालेकर,श्याम राजौरे रामसिंग यादव,महेश सीटोले सहित साथिगनो ने सहभागिता निभाई ।

विभाग के लोगों को भी किया जाएगा आइसोलेट

माही की गूंज, झिरन्या। दुर्गेश पिता महेंद्र इंदौर सब्जी मंडी में अदरक आदि बेचने का कमीशन पर काम करता था। पिछले माह 22 मार्च को झिरन्या आया था। यहाँ के शास. हॉस्पिटल में डबल टाइफाईड और टीबी का इलाज चल रहा था। आइसोलेटेड के बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को जो सम्बधित का ईलाज कर रहे थे, को भी आइसोलेशन वार्ड में भेजना होगा। ग्राम मारूगढ़ होगा हॉटस्पॉट झिरन्या के आमजन को रहना होगा।

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने गेंहु उपार्जन केंद्रों का किया ओचक निरीक्षण

माही की गूंज, भीकनगांव/बमनाला। तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी एवं नायब तहसीलदार ममता मिमरोट ने बमनाला कृषि उपज मंडी पहुंचकर गेंहू उपार्जन खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। किसानों तुलावटी, हम्मालों सहित गेहूं खरीदी केंद्रों में तैनात कर्मचारियों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व मुंह पर मास्क व हाथ धुलाई सेनेटाइजर के उपयोग करने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायतो को खरीदी केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था व सेनेटाइजर छिड़काव के निर्देश दिए। खरीदी केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से भीड़ नही इकट्ठा होने की हिदायत भी दी गयी। वहीं कृषि उपज मंडी में सुबह से खरीदी केंद्र पर थाना मोबाईल के द्वारा सोशल डिस्टेंसीग बनाए रखने की मुनादी भी की गई।

मंगलवार को 41 लोगों ने घर बैठे मंगाया किराना सामना

अभी तक इस सेवा का लाभ ले चुके है 402 लोग

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले में टोटल लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों को घर बैठे किराना सामग्री मंगाने की दी गई सुविधा का लाभ लेते हुए मंगलवार को बड़वानी नगर के 41 लोगों ने आर्डर देकर लाभ उठाया है। नगर पालिका सीएमओ कुशलसिंह डोडवे से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक इस योजना से 402 लोगों ने आर्डर देकर अपने घर बैठे सामान बुलवाया है।

एसडीएम बड़वानी अंशु जावला से प्राप्त जानकारी अनुसार टोटल लॉकडाउन के मद्देनजर लागू धारा 144 के तहत लोगों का किराना दुकानों पर भी जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिका के माध्यम से किराना सामान की डिलेवरी प्रातः 8 से 11 बजे तक घर-घर की जा रही है। इसके लिए नगर के वार्ड क्रमांक 1 से 6 के लिए गोविन्द सोनी मोबाईल नम्बर 9893801684, वार्ड क्रमांक 7 से 12 के लिए रामकरण डावर मोबाईल नम्बर 9174361255, वार्ड क्रमांक 13 से 18 के लिए शैलेष मायरिया मोबाईल नम्बर 9424007065 तथा वार्ड क्रमांक 19 से 24 के लिए अंकित पुरोहित मोबाईल नम्बर 7828670132 को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक आर्डर बुक कराया जा सकेगा। जिसकी सप्लाई दूसरे दिन प्रातः 8 से 11 बजे तक की जा सकेगी । एक परिवार सप्ताह में एक बार ही अपना आर्डर बुक करा सकेगा।

इसी प्रकार दूध की डिलेवरी का समय प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं शाम 7 से 8 बजे तक रहेगा। दूध को भी लेने हेतु कोई दुकान या डेयरी तक नही जा सकेगा। उक्त अवधि में इनका वितरण भी घर - घर ही किया जाएगा।

ओंकारेश्वर में उड़ रही खुले आम लॉकडाउन की धज्जियां

माही की गूंज, ओंकारेश्वर। देश में कोरोनावायरस संक्रमण रोग के संकट से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई है।

ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के सार्वजनिक स्थान बालवाड़ी पुराना बस स्टैंड ब्रम्हपुरी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर बेवजह फालतू घूमते हुए सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। इनके द्वारा खुलेआम लॉकडाउन का माखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे तत्वों पर पुलिस ने शक्ति से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ देश इस महामारी को झेल रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। सहयोग करना तो दूर यह से तत्व व्यवस्थाएं और बिगाड़ने में लगे हुए हैं।

कांग्रेस और भाजपा दवाइयों पर भी कर रही घृणित राजनीति

सरकारी गोलियों के प्रदाय को लेकर सीएमएचओ बने राजनीति के शिकार

माही की गूंज, झाबुआ।

एक तरफइन दिनों जहां पूरा देश नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस बीच भी झाबुआ जिले में दो प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। दोनों ही पार्टियां जिले की जनता के लिए अपने-अपने स्तर पर पहल कर जिले में कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु सार्थक पहल तो कर रहें है, पर इसी बीच दोनों ही पार्टियां इस आपातकाल और संकट की घड़ी के बीच भी एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी पीछे नहीं रह रही है। बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में राजनैतिक पार्टियों को बजाय इसके की मिलकर काम करें, एक दूसरे पर छीटाकंशी करने एवं आरोप-प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए है। मामला जिला चिकित्सालय झाबुआ में 12 अप्रैल, सोमवार को क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया एवं उनके पुत्र जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष तथा विधायक प्रतिनिधि डॉ. विक्रांत भूरिया द्वारा जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस की प्राथमिक उपचार की हाईड्रोऑक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट की 7 हजार टेबलेट, चिकित्सायतन प्रबंधन को प्रदान करने का है। जिला युवक कांग्रेस एवं विधायक प्रतिनिधि डॉ. विक्रांत भूरिया द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. बीएस बघेल एवं आरएमओ डॉ. सावनसिंह चौहान को यह टेबलेट्स बॉक्स प्रदाय किए गए।

जिला भाजपा ने कहा मप्र शासन की ओर से दवाई उपलब्ध करवाई

जिसके मीडिया में समाचार प्रकाशन होने के बाद यह जिला भाजपा को हजम नहीं हुआ और इस संबंध में क्षेत्रीय सांसद गुमानसिंह डामोर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीम प्रकाश शर्मा ने तत्काल इस संबंध में प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से

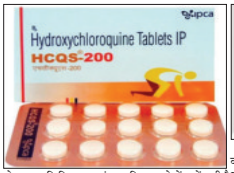

रोकथाम की यह 7 हजार टेबलेट गत 11 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस बारिया को अधिष्ठाता महात्मा गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय इंदौर से उपलब्ध करवाई गई। यह टेबलेट वर्तमान मप्र सरकार के प्रयासों से जिला चिकित्सालय प्रबंधन को उपलब्ध हो पाई है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया एवं उनके पुत्र डॉ. विक्रांत भूरिया ने जबरन वाहवाही लूटने की दृष्टि से जिला चिकित्सालय पहुंचकर डॉ. विक्रांत भूरिया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऐसे फोटो खिंचवाकर कि यह टेबलेट्स उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। इसे प्रेस में जारी करते हुए जबरन जिले की जनता के समक्ष यह दिखाने का प्रयास किया कि वे एवं उनकी पार्टी जिलेवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से कितनी गंभीर है।

पिता-पुत्र लोगों की झूठी सिमपेथी ले रहे

बाद में सांसद गुमानसिंह डामोर ने भी इस संबंध में मीडिया में व्यक्त्य दिया कि क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल भूरिया, उनके पुत्र और कांग्रेस पार्टी ऐसी महामारी के बीच भी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे है। जनता के सामने अपनी छवि साफबताकर झूठा का सहारा लेकर यह साबित करने का प्रयास कर रहे है कि कांग्रेस पार्टी हर परिस्थितियों में जिले की जनता के साथ है। सांसद डामोर ने कहा कि यदि विधायक एवं उनकी पार्टी जिले की जनता की मदद ही करना चाहती है, तो अपने स्तर पर एवं अपने खर्चे से कार्य कर उसका सार्वजनिकरण हासिल करने में क्यों लगी है?

विधायक पुत्र ने भी दिया करारा जवाब

इसके बाद इस मामले में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि डॉ. विक्रांत भूरिया ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर इसका करारा जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने साफतौर पर कहा कि जब क्षेत्र के विधायक होने के नाते कांतिलाल भूरिया एवं हमारी पार्टी जिले की जनता की विपदा की इस घड़ी में उनकी मदद करने में लगी है। तो यह सांसद एवं भाजपा जिलाध्यक्ष को रास नहीं आ रहा है। सांसद एवं भाजपा जिलाध्यक्ष जिला चिकित्सालय पहुंचकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन को यह धमका रहे है कि आप विधायक एवं उनके पुत्र को जिला चिकित्सालय बेवजह क्यों बुलवा रहे है। जबकि चिकित्सकों को धमका-धमका कर उनसे कार्य करवाया जा रहा है।

अभी राजनीति करने का वक्त नहीं

डॉ. विक्रांत भूरिया ने इस वीडियों में भाजपा को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अभी फिलहाल वक्त राजनीति करने का नहीं है। वर्तमान समय देश के हित के बारे में सोचना का है, मिलकर कार्य करने का है। यदि भाजपा मिलकर कार्य नहीं कर सकती, तो कम से कम समय हम जो क्षेत्र एवं जिले में जनता की इस विभारी से सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे है, उस पर रस्सा-कस्सी और छीटाकंशी न करें। डॉ. भूरिया ने कहा कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है, इसलिए कांग्रेस चुप बैठी है। देष को इस संकट की घड़ी से उबरने के बाद पार्टी इसको मुंहतोड़ जवाब देगी।

सीएमएचओ आए बेकफुट पर

उधर इस संपूर्ण मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस बारिया भी बेकफुट पर आ गए है। डॉ. बीएस बारिया एक तरफकह रहे है कि कोरोना वायरस से रोकथाम की यह 7 हजार टेबलेट स्वास्थ्य विभाग को अधिष्ठाता महात्मा गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय इंदौर से प्राप्त हुई है। यहीं बात उन्होंने भाजपा से चर्चा में कहीं है, तो दूसरी ओर डॉ. विक्रांत भूरिया की ओर से जारी वीडियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह भी अपना बयान देते हुए कह रहे है कि यह दवाई क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से इंदौर मेडिकल कॉलेज से उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में सीएमएचओ डॉ. बारिया का दो पक्षीय रूख एवं दो पक्षीय बयान भी समझ से परे है?

क्या यह समय राजनीति का है?

इस संबंध में हम जिले की जनता से पूछना चाहते है कि क्या कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव हेतु जब संपूर्ण देश में लॉकडाउन के साथ झाबुआ जिला भी संपूर्ण लॉकडाउन है, तो क्या इस बीच दो प्रमुख जिम्मेदार पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना सही है। क्या फर्क पड़ता है कि यदि इंदौर मेडिकल कॉलेज से कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु आई 7 हजार टेबलेट्स क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस की ओर से प्रदाय की गई हो, या क्या फर्क पड़ता है कि यह वर्तमान भाजपा सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई है। अभी तो फिलहाल दोनो ही पार्टियां को एकजुट होकर जिले की जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करने की आवष्यकता है। बजाय इसके बेवजह आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है।

जिले में बाहर से आये 5 से 6 लोग शव यात्रा में शामिल हुए

सूचना मिलते ही सभी को किया गया कोरोनाटाईन

माही की गूंज, झाबुआ।

देश में इस समय लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है कोरोनावायरस की वजह से दिन-ब-दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है जहां देखो वहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है ऐसी स्थिति में झाबुआ में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां के राधा-कृष्ण मार्ग में एक शव यात्रा में शामिल होने अन्य जिलों के करीब 5 से 6 व्यक्ति पहुंच गए 1 दिन बीत जाने के पश्चात प्रशासन को सूचना मिली तो प्रशासनिक अमले ने आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर सभी अन्य जिलों से आए हुए व्यक्तियों की जांच करें एवं उनके सैंपल एकत्रित किए गए और उन्हें हिदायत दी गई कि घर के सभी व्यक्ति को घर पर ही क्वारिंटाइन में रहे एवं किसी से मेलजोल कर बाहरी व्यक्ति के संपर्क में ना रहे प्रशासन के इस कार्य की नगर में बहुत सराहना है हो रही है लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिले के चारों तरफनाकेबंदी के बावजूद अन्य जिलों के व्यक्ति अपने निजी वाहन से इस जिले में कैसे प्रवेश कर गए सोचने का विषय यह है कि पुलिस प्रशासन के मुस्तैद होते हुए यह बाहरी लोग झाबुआ जिले में इतनी आसानी से प्रवेश कर गए सोचने में यह भी आता है कि अगर इन लोगों में से एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो जिले में क्या होगा यहां आप अच्छी तरह से सोच सकते हो शव यात्रा में कई लोग सम्मिलित हुए होंगे नियमों के मानो तो सभी व्यक्तियों को होम क्वारिंटाइन होना चाहिए जिससे आगे खतरा बढ़ने से रोका जा सके और प्रशासन को और मुस्तैद होना चाहिए कि अन्य जिले का व्यक्ति झाबुआ जिले में प्रवेश न कर सके क्योंकि झाबुआ जिला अभी तक ग्रीन जोन में आ रहा है और अगर यहां पर एक भी व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो जिला ग्रीन जोन में नहीं रहेगा।

पुलिस जवानो एवं अस्पतालकर्मियो के साथ ही लोगो को पिला रहे ताजी चाय

माही की गूंज, झाबुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों एवं असहाय लोगों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाने तथा उनकी मदद के साथ ही भोजन, चाय , नाश्ता आदि की सहायता उपलब्ध कराने का आव्हान किया है। इसका असर आदिवासी अंचल झाबुआ में भी दिखाई दिया। स्थानीय अटल कॉम्प्लेक्स स्थित दूध डेयरी के मालिक नारायण एवं उनके मित्र सोनू द्वारा मानव सेवा ही माधव सेवा के महामंत्र को जीवंत करते हुए नगर के चौराहों पर स्थित ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं जिला चिकित्सालय के सभी वार्ड में भर्ती मरीजों को चाय का वितरण कर रहे है। इनकी इस मानव सेवा को लेकर जहां पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों ने इस कार्य को लेकर उनकी प्रशंसा की है। वही क्षेत्रिय सांसद गुमानसिंह डामोर ने भी उनकी नर सेवा को नारायण सेवा के रुप में बताया।

घर पर रहकर चारकोल से बनाई पेंटिंग

माही की गूंज, झाबुआ। शहर के लक्ष्मीबाई मार्ग में जैन मंदिर के समीप रहने वाले बाल कलाकार अनंश अतिम जैन (पोरवाल) उम्र 16 वर्ष ने कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु जिले में लगे लॉकडाउन के बीच अपने घर पर ही रहकर चारकोल से ड्राईंग शीट पर एक उम्दा चित्रकारी की है। जिसमें उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध महिला का चित्र बनाकर उसकी मर्म स्पर्शता को बखूबी प्रदर्शित किया है।

बेरोजगारी से तंग आकर फॉलेन आउट अतिथि विद्वान ने की जीवनलीला समाप्त

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय नेहरू महाविद्यालय बुदावर जिला शाहडोल में अतिथि विद्वान

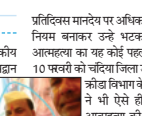

ऋीडा अधिकारी अजय त्रिपाठी ने चार दिन पूर्व आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के चलते फॉसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव दो दिन तक पँदे पर ही लटका रहा,सोमवार को बदबू आने पर आस पडोस के लोगो ने दरवाजा तोड़कर देखा तथा शव को नीचे उतारा गया।

बताया जाता है कि पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा दिसंबर माह में पीएससी से 3148 उम्मीदवारों की नियुक्ति होने से 2710 अतिथि विद्वान फॉलेन आउट हो गये थे। उसमें दिवंगत अनिल त्रिपाठी भी बुदार कॉलेज से फॉलेन आउट होकर भोपाल में चल रहे आंदोलन में शामिल थे,परंतु सम्पूर्ण लॉकडाउन के चलते वह अपने घर चले गये थे। पूर्व कॉग्रेस सरकार द्वारा नियमितीकरण का वचन नही निभाने के विरोध में 135 दिन से सभी भोपाल के शाहजहाँनी पार्क में आंदोलन कर रहे है। उच्च अर्हता धारक का आत्महत्या करना समाज के लिए शर्मनाक है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए उच्च शिक्षित नौजवानों को प्रतिदिवस मानदेय पर अधिक समय तक रखती है। फिर नये नियम बनाकर उन्हे भटकने के लिए छोड़ देती है। आत्महत्या का यह कोई पहला मामला नही है, इससे पूर्व 10 फरवरी को चांदिया जिला उमरिया में सरकारी कॉलेज के ऋीडा विभाग के अतिथि विद्वान संजय कुमार ने भी ऐसे ही कारणो से फाँसी लगाकर आत्महत्या की थी। आंदोलन के दौरान ही चार अतिथि विद्वान और दो बच्चे बीमार होने से अपनी जीवनलीला समाप्त कर चुके है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं ने इनका पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इनके विषय में अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। कमलनाथ सरकार के वचन से सभी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि समय रहते इनके विषय में उचित निर्णय नही लिया जाता है,तो नौकरी डर अन्य लोगो पर भी प्रभाव डाल सकता है। शासकीय पीजी कॉलेज झाबुआ के फॉलेन आउट अतिथि विद्वान शंकरलाल खरवाडिया का कहना है कि, पाँच माह से आर्थिक बदहाली और नौकरी के गम ने अंदर से कमजोर कर दिया है। पारिवारिक निर्वाह के लिए सीएम साहब को फॉलेन आउट अतिथि विद्वानो की भी आर्थिक मदद करनी चाहिए।

झोलाछाप पर कार्रवाई, बंगाली डॉक्टर हुआ फरार

माही की गूंज, बनी। लॉक डाउन में बंगाली डाक्टर्स की शिकायत पर ग्राम बनी में प्रशासन ने छापा मारा। जिसमें झोलाछप बंगाली डॉक्टर फरार हो गया। गांव के लोगों की शिकायत पर पेटलावद बीएमओ डॉ. चोपड़ा. रायपुरिया के डॉ कटारा ने गांव में एक बंगाली डॉक्टर के यहां छापा मारा। इस कार्यवाही के दौरान झोलाछप डॉक्टर पीछे के रास्ते से फरार हो गया। डॉ. चोपडा इस झोलाछप डॉक्टर की शिकायत झाबुआ सीएचएमओ के यहां की गई थी। जिस पर हमारे द्वारा यह कार्यवाही की गई है। झोलाछप अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं दिल्ली से बनी में आए मानसिंग नामक व्यक्ति को बीएमओ डॉ.चोपड़ा, डॉ. कटारा और रायपुरिया पुलिस ने गांव के कोटवार के साथ पेटलावद कॉरिंटाईन सेंटर में जांच के लिए भेजा। मानसिंग टमाटर की गाड़ी चलाने का काम करता है और गांव बनी की लड़की के साथ शादी कर रखी है। मगर पूरे देश में लॉक डाउन होने पर दिल्ली से बनी गांव में आना कई सवाल खड़े करता है। इसको लेकर रायपुरिया पुलिस को सूचना दी गई थी। जिस पर उसे स्वास्थ्य जांच के बाद कॉरिंटाइन सेंटर भेजा गया।

लोगों को जागरूक कर बांटे मास्क

माही की गूंज, बामनिया। लॉक डाउन बढ़ने के बाद लोगों को जागरूक करने और शासन द्वारा जरूरी किए गए मास्क के लिए जनप्रतिनिधि आगे आकर लोगो को फ्री में मास्क बाट कर कोरोना वाइरस के बारे में जानकारी दी। युवा गरबा समिति द्वारा अमरगढ़ रोड सहित नगर के ग्रामीण बस्ती में मास्क बांटे। उक्त कार्य में समाजसेवियों ने भी अपनी ओर से मास्क उपलब्ध करवाए। समिति द्वारा लगभग 800 मास्क वितरित किये गए। इससे पहले ग्राम पंचायत की ओर से भी नगर के ग्रामीण इलाकों निःशुल्क मास्क वितरण का कार्य किया गया। कार्य में कमलेश बम, अजय जैन, सत्यनारायण शर्मा, सुमित अग्रवाल, खुशवंत डामर सहित समिति सदस्यों का सराहनीय सहयोग रहा।

आरोग्य सेतु एप में कोरोना वायरस के बचाव के लिए कारगार उपाय

माही की गूंज, झाबुआ।

भारत सरकार ने कोरोना वायरस पर अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु एप लांच किया है। कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने अवगत कराया कि सक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आते ही यह एप उपयोगकर्ता को सतर्क करेगा। यह एप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। यह एप इस तरह डिजाइन किया गया है जो आपकी निजता का ख्याल रखेगा। इस एप के प्रचार-प्रसार के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक लाख लोगों को एसएमएस भेजा जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एक मात्र एवं कारगर उपाय है। कोरोना होने पर घबराये नहीं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या हेल्प लाईन नम्बर 104व181 पर सम्पर्क करें।

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कपिल कुमावत ने बताया कि यह एप एण्ड्राइड और आईफोन दोनो तरह के स्मार्ट फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप में ब्लूटुथ तकनीक अलगोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। ब्लूटुथ तकनीक एवं लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफकी मदद से यह एप कोरोना पॉजिटिव लोगो के साथ आपके संभवतः सम्पर्क को ट्रेककर्ता है तथा अलर्ट के माध्यम से आपको सतर्क करेगा।

ऐसे करे आरोग्य सेतु एप को डाउन लोड

यह एप डाउन लोड करने के लिए एप स्टोर में जाकर आरोग्य सेतु टाइप करे अथवा नीचे दी गई लिंग को ब्राउजर में ओपन करें। एण्ड्रायेड्ड व आईओएस में उपलब्ध है। एप डाउन लोड करने के बाद एप को ओपन करे तथा अपनी पसंद की भाषा चुने। इसके बाद नया पेज खुलेगा। उसको ध्यान से पढकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। अब एप आपसे ब्लूटूथ तथा जीपीएस लोकेशन डेटा की अनुमति मागेगा। यह एप तभी काम करना है जब आप अपने मोबाईल नम्बर को रजिस्टर करते है और ओटीपी को वेरीफई करते है, तब एक विकल्प फॉर्म भी आता जो नाम, उम्र, पेशा और पिछले 30 दिनों के दौरान विदेशी यात्रा के बारे में पूछता है। आप यहां वालेंटीयर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते है।

ऐसे दिखता है खतरा

यह एप हरे और पीले रंग के कोडो में आपको जोखिम का स्तर दिखाता है। साथ ही यह सुझाव भी देता है कि आपको क्या करना है।

प्राइवेसी बनाम रोग की सुरक्षा के बीच विश्वास जरूरी

कोरोना वायरस से फैली दहशत के बीच कहा जा सकता है कि ये वक्त ध्यान भटकाने वाले मुद्दे उठाने का नहीं है। वैसे भी संभावना यही है कि ऐसे उठाए गए मुद्दों पर ज्यादातर जागरूक लोग भी अभी ध्यान नहीं देंगे। सरकारों से उम्मीद तो बेजा है, जिनकी मंशा पर ये सवाल खड़े किए गए हैं। बहरहाल, ये सच है कि विश्व के और कई देशों की तरह भारत में भी इन दिनों कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप पर प्राइवेसी बनाम रोग से सुरक्षा की बहस चल पड़ी है। महामारी के फैलाव की गति उसे रोकने की सरकार की कोशिशों से तेज है। इसलिए सरकारें टेक्नोलॉजी की मदद ले रही हैं। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम का ऐप जारी किया है। सरकार पूरे देश के लोगों से उसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के लिए कह रही है। सरकार का कहना है कि इस ऐप में कोविड-19 से जुड़ी सभी जानकारी के अलावा एक बहुत ही काम का फीचर है। अगर इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने फोन का ब्लूटूथ और जीपीएस ऑन कर दें और ऐप पर अपनी लोकेशन शेयर कर दें, तो ऐप आपको बता देगा कि आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के पास गए थे या नहीं।

गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को एक करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। कई राज्य सरकारें भी अपने अपने ऐप बना रही हैं और उनका इस्तेमाल कर रही हैं। मगर निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार के लिए संघर्षरत कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों की राय है कि अगर सरकारों को इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करना है, तो उन्हें इसके लिए एक कानूनी प्रेमवर्क तय करना चाहिए। उसमें कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए- मसलन, किस अधिकारी की इजाजत से ऐप के जरिए लोगों का डेटा लिया जा रहा है, लोगों का कौन-सा डेटा लिया जाएगा और कौन सा नहीं, ये कहां स्टोर होगा और किस-किस की इस तक पहुंच होगी इत्यादि। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नामक संस्था ने इसे चिंताजनक बताया है कि सरकारें मोबाइल के लोकेशन डेटा को इस्तेमाल करने का कानूनी आधार नहीं बता रही हैं। ये वक्त कठिन है। इस मौके पर सरकारों की चुस्ती तभी कामयाब होगी, जब उसके प्रति लोगों का मजबूत भरोसा हो। इसलिए सरकारों को चाहिए कि इस वक्त वे संदेह पैदा करने वाले तमाम सवालों के संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करें। यही सबके हित में होगा।

कोरोना सप्तपदी के साथ बंधा अवाम

राकेश अग्रवाल
वरिष्ठ स्तंभकार

समय ऐसा है कि सरकार के किसी भी कदम के विरुद्ध कुछ कहा नहीं जा सकता। हां में हां मिलाना ही अब राष्ट्रवाद है। विश्वव्यापी कोरोना संकट से निबटने के लिए केंद्र ने आज पिछ तीन सप्ताह का सकल लॉकडाउन का ऐलान किया है। हम न इसका स्वागत करते हैं और न विरोध क्योंकि आज ही हमारी आंखों के सामने 22 साल की एक लड़की के दुधमुहे बच्चे का मुरझाया चेहरा था, जिसे दो दिन से खाने को कुछ नहीं मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट से जूझने में अपने आपको युग-पुरुष घोषित करने का अनजाना प्रयास न भी कर रहे हो, लेकिन आज स्थिति ये ही है कि कोरोना के खिलाफउठाये गए सरकारी कदमों से यदि लोग मौत के मुंह में जाने से बचे भी हैं, तो उन्हें मौत ने भूख और बेरोजगारी के रूप में अपना शिकार बना लिया है। स्थिति भयावह है क्योंकि अब असहाय महिलाएं अपने बच्चों को भूख से तड़पता न देखकर उनकी हत्या करने पर विवश हो रहीं हैं। लेकिन लाकडाउन की मियाद बढ़ाते समय ऐसे लोगों के बारे में कोई स्पष्ट सन्देश नहीं दिया गया है।

कोरोना संघर्ष को लेकर मैदान में डटे सरकारी अमले की नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं भी नहीं, क्योंकि वे इस आपदा के समय में जितना कुछ बेहतर कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नीतियां व्यावहारिक नहीं हैं। हकीकत ये है कि हम अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर अपनी पाककला का शानदार प्रदर्शन तो करने में लगे हैं, लेकिन हमें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। हम जो खबरें लिखते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचवन देते हैं, छह क्या बारह सप्ताह का लॉकडाउन झेल लेंगे, लेकिन उनका क्या जिनके पास एक दिन का खाना नहीं है?

सरकार ने लॉकडाउन लागू करते समय भी भावी व्यवस्थाओं का सही आकलन नहीं किया था। जिसका खमियाजा पूरे देश के गरीब मजदूरों-किसानों ने भुगता और अब दूसरे चरण के लॉकडाउन के समय भी पूर्व में सामने आई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया गया। गांवों की तो छोड़िए संभाग मुख्यालयों पर जनता परेशान है। किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास राशन। सड़क पर निकले तो लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप और पुलिस की लाठियां जरूर हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन विश्वास कीजिये कि मैं 22 मार्च से अपने घर के बाहर नहीं निकला, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा वाट्सअप दुर्दशा की सूचनाओं से अटा पड़ा है। खुद मेरे पास नगदी समाप्त है, एटीएम जाने का साहस नहीं, पता नहीं कब पुलिस कचूमर निकाल दे। किरायेदार ने किराया नहीं दिया और सरकार का वृद्धा निधि खाता मुंह चिढ़ा रहा है।

लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान कोरोना मरेगा या नहीं, लेकिन अवाम को जरूर मरना पड़ेगा। भूख से, लाचारी से, महामारी से। एक शहर से दूसरे शहर की तो छोड़िये। आप एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले तक नहीं आ-जा सकते। अपने वाहन से छोड़िये पैदल नहीं आ -जा सकते। युद्धकाल में भी ऐसी दुरूह परिस्थितियां देश ने नहीं देखी। लेकिन मजबूरी का नाम कोरोना है। सब जानते हैं कि हम गरीब देश हैं और हमारे पास न आपदाओं से जूझने के संसाधन है और न महामारियों से निबटने के साधन। हम चाहे जितनी सफाईयां गांठ से बाँध लें लेकिन सामने मुंह खोले खड़ी चुनौतियों से जूझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इस बात की सुविधा है कि हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को आरोपित कर लें, लेकिन हम अपनी उपलब्धियों और खामियों के बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं।

अर्थव्यवस्था की कीमत मनुष्यता बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते की संघर्ष और संसाधनों का साथ सतत चलता है। इसे रोक कर आप विजयश्री हासिल नहीं कर सकते। लोग कोरोना से बच जाएं और भूख से मर जाएं, ये कौन सा कल्याणकारी राज्य का फार्मूला है? जिन राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की मियाद प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय उदबोधन से पहले ही बढ़ा दी थी, वे भाजपा की सरकारें नहीं थीं। उनकी मजबूरी थी और यही मजबूरी पूरे देश की मजबूरी बन गई।

लोग सौने पर पत्थर रखकर भूखे बैठे हैं। अपने सगे-संबंधियों की अंत्येष्टियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये कैसी हृदयहीनता है। आपके अस्पताल इन दिनों कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी का इलाज करने को तैयार नहीं है। निजी क्लिनिक बंद हैं। ऐसे में बच्चे और बूढ़े आखिर जाएं तो जाएं कहां? उनका तो कोई मालिक ही नहीं है। इस आपदा में जो समर्थ हैं, वे ही जिंदा हैं। बाकी सब अभिशप्त, राम जी के भरोसे।

मैं फिर से प्रधानमंत्री जी के निर्णय को राष्ट्रहित में मानकर उसका समर्थन करते हुए दोहराना चाहता हूं कि सरकारें हकीकत से मुंह न मोड़ें, व्यावहारिक फैसले लें। हमें कोरोना और भूख से एक साथ लड़ना है। दोनों ही मोर्चे तब चलते होंगे, जब हम पहले भूख का मोर्चा न हारें। भूखे पेट जब भजन नहीं हो पाता, तब कोरोना से संघर्ष कैसे होगा। कल्पना की जा सकती है? नई सप्तपदी में बंधे हम लोग एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे लेकिन कब तक? जब जान और जहान दोनों होंगे तब न !

लॉकडाउन में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब

माही की गूंज, थांदला। नगर में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं। जगह-जगह अवैध शराब की जहां बिक्री हो रही है, वहीं जुआ भी संचालित हो रहा है। जुए की फड़ में लोगों के झुंड बनाकर बैठने से संक्रमण भी बढ़ सकता है। नगर के कई वार्डों के अलावा ग्रामीण बस्तियों में भी कुछ लोग अवैध शराब बिक्री के साथ जुआ भी संचालित कर रहे हैं। मनमाने दाम पर लोगों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ दिन पहले ही पेटलावद मार्ग पर विदेशी शराब दुकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा टिन शेड काटकर शराब की चोरी कर ली गई थी। इधर, सोमवार को आबकारी अमले ने गश्त के दौरान ग्राम वट्ठा, बलवासा, काकनवानी, देवका से 2 पेटी अवैध विदेशी मदिरा बीयर तथा 25 पाव प्लेन मदिरा जब्त कर 4 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ज्ञात हो कि यह क्षेत्र गुजरात बाउंड्री से कुछ ही दूरी पर है और यहां से शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता है। ग्राम काकनवानी, देवका, वट्ठा, बलवासा शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 हजार बताई जा रही है। आबकारी उपनिरीक्षक किरण निनामा ने बताया कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के आसपास गश्त तथा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों पर कार्रवाई निरंतर जारी है।<

पुलिस से पकड़ी 40 हजार की अवैध शराब

माही की गूंज, पेटलावद। ग्राम भाभरपाड़ा में लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना पर आबकारी टीम ने आरोपी लक्की उर्फलवलेश बसेर के यहां से देशी एवं अंग्रेजी शराब करीब 40 हजार रुपए की शराब जप्त की है। इस कार्यवाही में निरीक्षक संजय रावत, उप निरीक्षक नरेश निनामा, प्रधान आरक्षक हितेन्द्र चन्द्रवंशी , आरक्षक अरूण डामोर , प्रधान आरक्षक राजेन्द्र , आरक्षक अमरसिंह, आरक्षक श्याम की टीम ने उक्त कार्यवाही की है। बसेर पर कोविड दृ 19 महामारी रोग जारी आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 , 269 , 270 भादवि एवं 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत थाना पेटलावद में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया है।

गेहूं उर्पाजन के लिए केन्द्रों का निर्धारण

माही की गूंज, झाबुआ। जिले में 15 अप्रैल 2020 से कृषकों से गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य हेतु जिलें मे 20 सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जन केन्द्र बनाए गए है। झाबुआ अनुभाग में झाबुआ, रानापुर, कल्याणपुरा, रजला, पारा, कालीदेवी, मेघनगर अनुभाग में मेघनगर एवं नौगावां, थांदला अनुभाग में थांदला, खवासा, पेटलावद अनुभाग में रायपुरिया, पेटलावद, बामनिया, सारंगी, झकनावदा, करवड स्थित केन्द्रों पर खरीदी की जाएगी। केवल एसएमएस प्राप्त किसानों से खरीदी की जाएगी। किसान बंधु मुंह पर मास्क-गमछा बांधें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उपार्जन केन्द्रों पर पीने के पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने यह अपील की है कि सभी पंजीकृत किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। खरीदी केन्द्र पर मैसेज प्राप्त होन के पश्चात ही आए।

कालाबाजारी पर करड़ावद में एसडीएम ने की कार्यवाही

माही की गूंज, पेटलावद। समपीस्थ ग्राम करडावद में किराना दुकानों पर कालाबाजारी संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद खुली। ग्राम करडावद में दुकानदार प्रवीण द्वारा की जा रही मुनाफाखोरी पर अनुविभागीय अधिकारी और इंदौर की खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर तोल कांटें जप्त किए गए। इसके साथ ही करडावद की कई दुकानों पर जांच की गई। ज्ञात हो कि लॉक डाउन के बाद से किराना सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। पेटलावद सहित आसपास के बड़े व्यापारी द्वारा किराना वस्तुओं में जरूरत से अधिक पैसा कमाने के चक्कर मे छोटे दुकानदारो को महंगा सामान दिया जा रहा है। जिससे छोटे दुकानदार अपना मुनाफा जोड़ कर बेचने पर मजबूर है। प्रशासन को जमाखोरी करने वाले बडे व्यापारियों पर कार्यवाही करना चाहिए। जिससे बड़े स्तर पर हो रही मुनाफाखोरी को रोका जा सके।

गूंज की पहल लाई रंग

पंचायत एवं ग्राम स्तर पर जाकर कियोस्क कर्मवीर कर रहे पैसा वितरण

माही की गूंज, खवासा। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ विकट स्थिति में भी करता है, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को कर्मवीर की उपाधि ही दी जाती है। कर्मवीर के रूप में हमारा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व प्रशासनिक अमला कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए अपनी पूरी ऊर्जा व मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन करने वाले गरीब परिवार इस विकट स्थिति में आर्थिक रूप से भी परेशान है। उनकी परेशानी को कुछ हद तक दूर करने के लिए खाद्यान्न व बैंक खातों में कुछ रुपया भी सरकार डाल रही है लेकिन बैंक में जमा इन रुपयों को भी लॉकडाउन के आदेश व प्रशासनिक सख्ती के कारण निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। वही बड़े कस्बों में व बैंकों में बड़ी भीड़ होकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिख रही थी। जिसे देख गूंज ने एक पहल की, कि क्यों ना यह पैसा उनकी ही ग्राम पंचायत स्तर व उनके ही ग्राम में जाकर बैंक में जमा रुपैया मिल जाए, तो किसी भी गरीब परिवार को बैंक से रुपए निकालने में परेशानी नहीं होगी। जिसके लिए खवासा की एसबीआई शाखा के मैनेजर पीएन भूरिया व मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के मैनेजर पंकज संचार के साथ कियोस्क संचालकों से बात की दोनों मैनेजर को गूंज की पहल सही लगी और उसी पहल के आधार पर दोनों मैनेजरो ने अपने-अपने कियोस्क संचालकों को क्षेत्र की सागवा, रत्री, परवाड़ा, तलावड़ा, बड़ी संगत, सेमलिया, भेरूगढ़, नाहरपुरा, धुमड़िया, रतनाली, देवगढ़ कुकडीपाड़ा, मादलदा आदि सभी पंचायतों में बैंक के कियोस्क कर्मवीर जाकर बैंक की छुट्टी होने के दौरान भी प्रतिदिन एक-एक गांव या पंचायत में 60-70 लोगों को पर्ची बांटकर राशि आहरण कर दे रहे हैं। उक्त कार्य में बैंक मैनेजर के साथ क्षेत्र के सभी पंचायत के सचिव एवं कोटवार का अहम योगदान है, और पूरी एहतियात व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्षेत्र में रुपैया वितरित किया जा रहा है। खवासा सहित सभी पंचायत के सचिव एवं ग्रामीणजन गूंज की इस पहल की सराहना कर रहे हैं।

फर्जी डॉक्टर की कारस्तानियां

लुकछुप: पहले आम जनता को अब प्रशासन को बनाया निशाना

माही की गूंज खवासा।

जब टीवी और मोबाइल का युग नहीं था, तब बच्चों द्वारा एक खेल-खेला जाता था लुक-छुप। जिसे स्थानीय भाषा में छिपम छाई भी कहा जाता था। इस खेल में खेलने वालो में से एक बच्चा कुछ दूर चला जाता था और बाकी सभी बच्चे छुप जाते थे और कुछ देर बाद वह दूर जाने वाला बच्चा सभी बच्चों को ढूंढता है और जो सबसे आखरी में मिलता है, वह इस खेल का विजेता माना जाता था। यह खेल अब लुप्त हो चुका हैं। लेकिन कुछ इसी प्रकार का खेल खवासा में बाहर से आए तथाकथित डॉक्टर (बंगाली) ने खवासा की आम जनता और प्रशासन के साथ शासन के निर्देशों को अपनी जेब की कठपुतली मानकर खेला। जिसमें अब तक तो वह सफल हो गया, लेकिन कहावत है कि 'बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी' आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया और उस पर प्रकरण दर्ज हो गया।

होम क्वारंटाइन करने के बाद डॉक्टर गुटखा लेने गया। बाद में मोहल्लेवासियों को बता रहा है झूठा।

मामला खवासा ग्राम के बंगाली उर्फझोला छाप डॉक्टर अजीत राय का है, जो प्रशासन को चकमा देते हुए विगत 8 अप्रैल की रात में इंदौर में रह रहे अपने पुत्र को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ले आया। लोगों की जागरूकता के चलते मामले का खुलासा हुआ। झोला छाप बंगाली डॉक्टर अजीत राय, खवासा में विगत कई वर्षों से रहकर अपनी तिकड़म और पहुंच के बलबूते, अवैध रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तथा भोली-भाली आम जनता का इलाज कर मोटी रकम जमा कर न केवल खवासा में बल्कि पश्चिम बंगाल के कोलकत्ता में भी मकान बना लिया। इस दौरान एक से अधिक बार उसके हाथ से केस बिगड़े, लेकिन गांधी छाप नोटो व नोटो के संबंधों के जरिए हर बार मामला रफा-दफा करता रहा और इस दौरान उसने माताजी की भक्ति के नाम पर ग्रामवासियों से भी अच्छा व्यवहार बना लिया। यही नहीं इस तथाकथित बंगाली डॉक्टर ने पूर्व में होलसेल के नाम पर मेडिकल खोला। जिसका इसी कलम ने खुलासा किया। जिसके बाद वह मेडिकल बंद हो गया। जिसके बाद अब अपनी बेटी के नाम पर यहां मेडिकल खोल कर, अब मेडिकल में ही अपना फर्जी क्लिनीक चला रहा है। इतना ही नहीं 8 अप्रैल को अपनी गाडी के आगे कांच पर माही मेडिकल स्टोर की स्लीप लगाकर अति आवश्यक कार्य बताकर लॉकडाउन में पुत्र को लेने के लिए इन्दौर तक जाने वाला अजित राय एक चिटफंड कंपनी लुक-छुप के नाम पर कई लोगों को अधिक पैसा कमाने का लालच देकर पैसे ऐंठ चुका है। कुछ समय तक तो यह कारोबार चला और लोगों को कुछ पैसा मिलने लगा तथा अधिक पैसा कमाने के चक्कर में और कई लोग इससे जुड़ गए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस कंपनी का कोई अता-पता नहीं है। यहां तक की कई बंगालियों से भी मोटी रकम ले ली और वह अपने जेब में रख लिए और कई लोगों का पैसा इसमें डूब चुका है। लेकिन डर के मारे लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इंदौर में 610 बिचोली मर्दाना, श्याम हाईट अपार्टमेंट में राजेश जैन के मकान में रह रहे अपने पुत्र विजय को लाने के बाद यह तथाकथित बंगाली डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस पर धारा 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल 9 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 14 दिन के क्वारेंटाइन पीरियड में पुत्र विजय के साथ 9 जनों को रखा गया है और अवधि पूरी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा।

गाड़ी पर माही मेडिकल का पर्चा लगाकर पुत्र को लेने पहुंच गया इन्दौर।

पडोसी को परमिशन होने की बात कह कर ले गया था साथ

8 अप्रैल को यह तथाकथित बंगाली डॉक्टर अपने पुत्र को लेने के लिए अपने पड़ोसी अंकित जैन को यह कहकर ले गया कि, मेरे पास अपने पुत्र विजय को लाने की परमिशन है और हम उसे लेकर तत्काल वापस आ जाएंगे। अंकित ने बिना जांच पड़ताल किए पड़ोसी धर्म निभाया और उसके साथ हो लिया। अब इसे सिस्टम में कमी ही कहेंगे कि ये दोनों रात में 9 बजे अपनी स्वयं की वैगनआर गाड़ी क्रमांक एमपी 45 सी 2434 लेकर लगभग 12 बजे बिना रोक-टोक इंदौर पहुंच गए तथा अपने पुत्र को बैठाकर वापस लौटने लगे। लेकिन वापसी में दो-तीन जगह पर इन्हें रोककर वापस लौटा दिया गया। तो तथाकथित शातिर डॉक्टर कच्ची पगडंडियों का इस्तेमाल करते हुए येन-केन प्रकरेण खवासा पहुंच ही गया।

स्वास्थ्य टीम ने तीनों के लिए सैम्पल। बुधवार तक नहीं आई जांच रिपोर्ट।

लेकिन जागरूक खवासावासियों के कारण यह घटना छिप नहीं सकी। इंदौर जैसे कोरोना संवेदनशील शहर से कोई आया है और उससे यह वायरस खवासा में भी फैल सकता है। इस डर और जागरूकता के कारण तत्काल पुलिस को माही की गूंज प्रतिनिधि ने सूचना दी और पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक्शन लेते हुए तथाकथित बंगाली डॉक्टर का मकान सील किया। मेडिकल टीम द्वारा उनके जांच सैंपल लिए गए और उन्हें 14 दिन के सेल्फक्वारेंटाइन पीरियड में रखा गया। पर इस कार्यवाही के एक घंटे बाद ही फर्जी डॉक्टक ने कार्यवाही की भी धज्जियां उड़ाते हुए मोहल्ले में दुकान पर गुटका पाउच लेने पहुंच गया। तो दुकानदार ने बिना पाउच दिए भगा दिया। मोहल्लेवासियों ने इस बात की पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद मोहल्लेवासियों को झूठा ठहराने का प्रयास किया। पर जब मोहल्लेवासी एक मत से कहने लगे की तू दुकान पर पाउच लेने गया था। जिसके बाद पुलिस ने सख्त हिदायत देकर घर के अन्दर ही रहने को कहा।

मामला सामने आने के बाद भी पुलिस को फर्जी डांक्टर करता रहा गुमराह

पूरा मामला सामने आने के बाद भी फर्जी डॉक्टर पुलिस को गुमराह कर कहता रहा कि मैं ही अकेला मेरे पुत्र को लेने के लिए गया था। लेकिन आम लोगों की सतर्कता के साथ माही की गूंज ने साथ में गए पडोसी को खंगाल लिया और गूंज ने मोबाईल से बात की उसके बाद उसने आपबिती बताई।

अंकित ने पुलिस को दिए बयान, कच्चे रास्ते से लाया डॉक्टर, दुर्घटना से भी बचे

जिसके बाद पुलिस चौकी पर स्वयं जाकर अंकित जैन ने बयान दिए और कहा कि, मैं अजीत राय का पडोसी हूं। अजीत राय मेरे पास रात करीब साठे 8 बजे आया और कहा कि, मेरे पुत्र विजय को इन्दौर लेने जाना है, जिसकी परमिशन मिल गई हैं। मैंने अजीत राय की बात पर बिना परमिशन देखे उसके साथ रात करिब 9 बजे उसकी गाडी चलाकर गया। अंकित ने पुलिस को बयान में बताया कि, मैं खवासा से ड्रायविंग सीट पर बैठा और इन्दौर से खवासा आने के बाद ही गाडी से नीचे उतरा, यानी कहीं भी रास्ते या इन्दौर में भी गाडी से नीचे नहीं उतरा। बयान में बताया, जाते समय बेटमा टोल टैक्स पर पुलिस ने रोका था। जिनसे डॉक्टर ने ही बात की और कुछ 100 डायल की रिक्वेस्ट जैसी कोई बात पुलिस को कही। वहा कि पुलिस ने कहा कि, यहा से तुम तो निकल जाओगे पर इन्दौर में आपको रोक लेंगे और हमें वहां से जाने दिया। विजय के द्वारा भेजी गई मोबाइल लोकेशन से हम वहां पहुंच गए और 15 मिनिट में डॉक्टर अपने लडके को लेकर अर्पाटमेंट से आ गया।

अंकित ने बताया कि वापसी में बेटमा टोल टेक्स पर स्टाफचेंज हो गया और उन्होंने वहां से निकलने से मना कर दिया। तब मुझे पता चला कि डॉक्टर के पास कोई परमिशन नहीं है और मुझे गुमराह करके डॉक्टर ले कर आया है। वापसी में गाडी टोल टैक्स से रिर्टन की। डॉक्टर ने टोल टैक्स से करीब आधा किलोमीटर वापस आने पर एक कच्चे रास्ते में गाड़ी लेने को कहा। वहां से करीब आधा किलोमीटर टोल के आगे मुख्य मार्ग पर आ गए। भैंसोला होकर माही नदी पहुंचे। जहां भी पुलिस ने सीमा क्रास नहीं करने दी। वापसी रिटर्न होकर डॉक्टर द्वारा बताए गए कच्चे रास्ते से बोलासा होकर रायपुरिया से खवासा करीब सुबह 4 बजे पहुंचे। रास्ते में एक जगह खन्ती में गाडी भी दुर्घटना ग्रस्त होते-होते बची।

उक्त बाप-बेटे की कारस्तानी के कारण पडोसी भी उलझ गया और उसके विरूद्ध भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने भले ही डॉक्टर के विरूद्ध लॉकडाउन व कलेक्टर के आदेश कि अवहेलना का मामला दर्ज कर लिया हो, पर फर्जी डॉक्टर के विरूद्ध गुमराह करने को लेकर धारा 420 का मामला भी दर्ज होना चाहिए। यह मांग ग्राम के लोगों द्वारा की जा रही है।

जिसने जिले को संकट में डालने का प्रयास किया, बता दें कि यह डॉक्टर जिले या जिले कि सीमा का ही घुसपैठिया नहीं है वरन् यह ऐसा फर्जी व घुसपैठिया है कि, इसने तो देश ही सीमा में भी घुसपेठ कर भारत में आकर रह रहा है।

बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया है तथाकथित बंगाली डॉक्टर

गूंज की विशेष रिर्पोट निरंतर...

3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जारी हुए नए दिशा-निर्देश

लॉकडाउन तोड़ने वालों पर होगी कार्यवाही

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

14 अप्रैल को समाप्त हुआ 21 दिनों के लॉक डाउन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इस कोरोना महामारी से बचने के लिए फिर से लॉक डॉउन को बढ़ाया गया और 03 मई तक कर दिया गया। जिले भर में कोरोना का फिलहाल एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं के लिए किसी प्रकार की छूट का समय नहीं दिया गया हैं और जिले में जारी सम्पूर्ण लॉक डॉउन को जारी रखा है। नए आदेश के चलते पेटलावद प्रशासन द्वारा14 अप्रैल तक के बने सभी पास निरस्त कर दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए जिला स्तर से नए पास जारी किए हैं। जिसके लिए इच्छुक व्यापारियों से आवेदन लिए गए। इस बार व्यापारी न केवल नगर बल्कि आस पास के ग्रामीण इलाकों में जा सकेंगे। जिससे ग्रामीणों को घर बैठे आवश्यक वस्तुओं की लेने की सुविधा मिल सकेगी। प्रशासन ने इस बार सब्जी, किराना, दूध सहित और भी पास जारी किए है। चूंकि कृषि कार्य शुरू है, इसलिए कृषि दवाई, बीज, कृषि यंत्र सुधारने हेतु मेकेनिक, लोडिंग वाहन आदि को भी पास जारी किये गये है। कोरोना का जिले में अभी कोई प्रभाव नहीं है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी आमजन की सुविधा को देखते हुए पास जारी किए ताकि लोगों को परेशानी न हो और ग्रामीणों को बाजारों तक नहीं आना पड़े।

20 के बाद मिल सकती हैं राहत

अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव पेटलावद विकास खण्ड में नहीं मिला हैं। देश के प्रधानमंत्री के उद्बोधन में कहा गया है कि जिस जिलों और थाना क्षेत्रों में 20 अप्रैल तक अगर कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलता तो स्थानीय प्रशासन अपने विवेक से निश्चित समय के लिए बाजार खोल ने निर्देश दे सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार से कोई कोरोना पीड़ित मिलता हैं, तो तुरंत आदेश निरस्त माने जाएंगे और लॉक डाउन जारी हो जाएगा। यदि 20 के बाद बाजार खुलते हैं, तो कई लोगों के लिए खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट भी टल जायगा।

मध्यम वर्ग सबसे अधिक परेशान

आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर लगभग सभी व्यापार व्यवसाय बन्द पड़े हैं। जिसे मध्यम वर्ग की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मध्यम वर्ग में अधिकांश ऐसे परिवार है जिनके पास शासन की कोई सुविधा नही पहुंच सकती और कई प्रकार के लोन और कर्ज में अपना व्यवसाय कर परिवार चला रहा है। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों के लिए कोई व्यवस्था या लोन पर ब्याज की छूट, बैंक किश्तों पर रोक, बच्चों की स्कूल फीस माफी या अन्य कोई व्यवस्था नहीं होने से दोहरी मार पड़ रही हैं। कई व्यापारियों का सामान दुकान में पड़ा पडा खराब हो रहा है और कई सामान आउट ऑफसेल होने की कगार पर है। ऐसे में आथिर्क संकट और ज्यादा बढ़ने की संभावना है । पेट के कारण कई व्यापारी कानून और परिवार को खतरे में डाल कर भी व्यापार करने पर मजबूर हैं । कृषि दवाई, बीज , ठंडा आईसक्रीम, सीमेंट, कॉस्मेटिक, मशीनरी से जुड़े और सब्जी और फ्ल के किसान आदि से जुड़े व्यवसाय चौपट हो चुके हैं। वही इन व्यवसाय से जुड़ा मध्यम वर्गीय मजदूर के लिए भी आथिर्क संकट खड़ा हो गया हैसरकार को इस गंभीर समस्या के समय मे हर वर्ग को सुविधा देने की आवश्यकता है । जिस और केंद ओर राज्य सरकार का धयान नही गया हैं ।

एक ओर डॉक्टर पूजे जा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ शैतान बने हुए हैं

शासकीय अस्पताल में डिलेवरी के नाम पर हो रही लूट

माही की गूंज, पेटलावद।

6 अप्रैल 2020 को पेटलावाद चिकित्सालय में एक महिला प्रसव के लिए आई। भूरी पति कैलाश ग्राम तीखी मठमठ। महिला को गम्भीर केस बताकर अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती किया जाता है। महिला को पेटलावद शासकीय अस्पताल की महिला विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। महिला एक बच्चे को जन्म देती है। यहां तक सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। जब 7 दिन के आवश्यक उपचार के उपरांत महिला को डिस्चार्ज करने की बारी आती है। डिस्चार्ज करते वक्त महिला से जो राशी मांगी जाती है वह घोर आश्चर्यजनक होती है।

खुद अगर भूरी के कथनों पर अगर गौर करें तो यह ग्रामीण के लिए आश्चर्यजनक है। भूरी बताती है कि उपचार के दौरान महिला डॉक्टर ने उससे 2 हजार की राशि ली थी। उसके अलावा 1300 की दवाई उसने केमिस्ट से खरीदी थी। भोजन वगैरह की व्यवस्था में उसकी समस्त जमा पूंजी लगभग 5 हजार इस इलाज में पूरी हो गई। और डिस्चार्ज के वक्त जब उससे 5 हजार रुपए की फिर से मांग हुई। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भूरी के परिजनों की जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पूरा भारत लॉक डाउन की स्थिति में है तो ऐसे में 5 हजार की व्यवस्था कहां से की जाए?

भूरी जैसी जाने कितनी गरीब आदिवासी महिलाओं से ये डॉक्टर पैसे निकलवाते होंगे। नियमानुसार भूरी के नाम मात्र रुपये इस केस में खर्च होने थे। शासन की ओर से मिलने वाली तमाम सुविधाएं पेटलावाद अस्पताल में उपलब्ध है। जिसमें दवाई से लेकर भोजन बिस्तर आदि सभी सामग्री भूरी को फ्री में मिलना थी। लेकिन इस महामारी के समय भी पेटलावाद अस्पताल के चिकित्सक महामारी के इस समय मे पहले ही अपने कार्य के प्रति लापरवाही कर नौकरी से दूरी बनाए हुए है, लेकिन अपनी निजी प्रेक्टिस और कमाई के कार्य में आज भी वहीं दिलचस्पी बनी हुई है। जहां पूरे देश में कोरोना वाइरस के चलते डॉक्टरों को भगवान माना जा रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर इस मुश्किल समय में अपने पाप धोने के बजाए अपनी शैतानी हरकतों से अभी भी बाज नही आ रहे हैं। यहां जो सबसे अधिक सोचने वाली बात है वह ये है कि लगभग 4000 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला डॉ सिर्फ200 रुपए रोज कमाने वाले गरीब को लूटता है।

ज्ञात रहे कि गत वर्ष भी एक प्रसव के केस में इन्ही लोगों ने एक गम्भीर भूल की थी। जिससे प्रसूता के लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी उसके बच्चे की जान चली गई थी। डॉक्टर की ढेरों शिकायतें स्थानीय और जिला स्तर पर दर्ज है, लेकिन सेटिंग करके ये सेटिंग मास्टर हर बार खुद को बचा लेते है। समय रहते इन भ्रष्टों के ऊपर अगर अंकुश नहीं लगा तो ये लोग गरीबों का खून चूसने से भी बाज नही आएंगे।

यह पहला अवसर नहीं है। जब कोई गरीब आदिवासी पीड़ित उक्त डॉक्टर के लालच का शिकार हुआ हो। पिछले वर्षों में ऐसे कई अवसर आए हैं। जब डॉक्टर ने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर पीड़ित गरीबों का जमकर शोषण किया हैं। प्रशासन ने कई बार इनके खिलाफमामले दर्ज किए परंतु हर बार अपने धनबल और पहुंच से हर मामला दबा दिया गया।

डिलेवरी केश में आई कमी

शासन की ओर से मिलने वाली सुविधा के चलते शासकीय अस्पताल में डिलेवरी केश लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते शासकीय अस्पताल में डिलेवरी केश में काफी कमी आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में पदस्थ कुछ कर्मचारी आने वाले डिलिवरी केस को महामारी की आड़ में डॉक्टरों की कमी और अस्पताल में महामारी के बीमार होने का हवाला दे कर निजी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। वही शासकीय जिम्मेदारी छोड़ कुछ डॉक्टर इस मौके को भुना कर माल बनाने में लगे हैं। ज्ञात है बीएमओ चोपड़ा अपनी ओर से ऐसे डॉक्टरों को नोटिस जारी कर समय पर अस्पताल में उपस्थित होने के लिए कह चुके हैं। इसके बाद भी कई डॉक्टर आज भी अपनी नदारद है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422